

03 \*सीएम केजरीवाल ने सपली बजरंग बली का दर्शन कर लिया

06 कृषि निर्यात बढ़ाने का मार्ग

08 अमित शाह बोले- बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा शब्दकोष

## सैटेलाइट आधारित टोल सिस्टम चरणबद्ध तरीके से होगा लागू, जानें कैसे कटेगा वाहन का टोल टैक्स

सरकार अगले सप्ताह वाहनों में ऑन-बोर्ड यूनिट (OBU) लगाकर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) पर आधारित टोल कलेक्शन शुरू करने जा रही है। जानें सैटेलाइट से कैसे कटेगा टोल टैक्स।

संजय बाटला

नई दिल्ली। एक बार जब यह नई प्रणाली सभी राजमार्गों पर पूरी तरह से चालू हो जाएगी, तो इससे भौतिक टोल प्लाजा या टोल गेट पर बिना रुके यात्रा करना संभव हो जाएगा। पूरी तरह से लागू होने में कुछ साल लगेंगे, लेकिन यह प्रणाली बेहतर हाईवे ड्राइविंग एक्सपीरियंस सुनिश्चित करती है। आइए जानें कि यह कैसे काम करेगा।

**सैटेलाइट द्वारा टैक की जाने वाली दूरी**  
इस नई प्रणाली का सबसे खास बात यह है कि यह उपग्रह (सैटेलाइट) या उपग्रहों का समूह वाहनों की आवाजाही को ट्रैक करेगा और यात्रा की गई सटीक दूरी के आधार पर टोल या उपयोगकर्ता शुल्क की गणना करेगा।

इसका मतलब है कि वाहनों को टोल बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से टोल काटने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, जैसा कि मौजूदा फास्टैग प्रणाली में होता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस सप्ताह की शुरुआत में GNSS-OBU प्रणाली का इस्तेमाल करके टोल कलेक्शन की अनुमति देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों में संशोधन किया। अधिकारियों ने कहा कि टोल प्रणाली भारत की उपग्रह-आधारित नेविगेशन प्रणाली NavIC का इस्तेमाल करेगी।

**पहले से इंस्टॉल किए गए उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा**

हर वाहन में एक गैर-हस्तांतरणीय GNSS-OBU यूनिट लगाई जाएगी। यह यूनिट एक ट्रैकिंग डिवाइस के रूप में काम करेगी। और इसे या तो बाहरी रूप से (रेट्रोफिट) लगाया जा सकता है या फैक्ट्री से लगी लगाई जा सकती है।

यह यूनिट 'केडीकेट' टोल चार्जर' सॉफ्टवेयर के साथ डिजिटल रूप से कम्प्युटिकेट (संचार) करेगी, जिसे निर्दिष्ट हाईवे खंडों पर स्थापित किया जाएगा। 'टोल चार्जर' वाहनों में लगे OBU से यात्रा की गई दूरी और समय के बारे में इनपुट हासिल करेगा। OBU को फिनटेक कंपनियों द्वारा टोल चार्जर से जोड़ा जाएगा, जो रजारीकर्ता इकाई के रूप में काम करेगा। ठीक उसी तरह जैसे FASTag सिस्टम के तहत जारीकर्ता बैंक होते हैं।

**वर्चुअल टोल बूथ**

हाईवे पर वाहनों के प्रवेश और निकास की ट्रैकिंग वर्चुअल गैट्री (एक तरह का सिग्नल इंफ्रास्ट्रक्चर) का इस्तेमाल करके की जाएगी। जिसे टोल वाले हाईवे नेटवर्क के साथ स्थापित किया जाएगा। यह सिस्टम GNSS के जरिए वाहनों से संवाद करेगा। वे एक वर्चुअल टोल बूथ के रूप में काम करेंगे जो वाहन पंजीकरण संख्या, उसकी टाइप और बैंक खाते के डिटेल्स जैसी



जानकारी इकट्ठा करेंगे।

जब GNSS-OBU वाहन वर्चुअल टोल बूथ से गुजरता है, तो सिस्टम मौजूदा FASTag इकोसिस्टम का इस्तेमाल करके यात्री के खाते से उपयोगकर्ता शुल्क को ऑटोमैटिक तरीके से काट लेगा।

जब भी कोई वाहन टोल प्लाजा की निर्धारित लंबाई को पार करेगा, यू-टर्न लेगा और GNSS स्ट्रेच को छोड़ेगा, तो उपयोगकर्ता शुल्क की रियल-टाइम में गणना की जाएगी। हर टोल कटौती पर उपयोगकर्ता को एक एसएमएस भेजा जाएगा। 'टोल चार्जर' NHAI (एनएचआई) द्वारा परिभाषित टोल मापदंडों जैसे कि संरचना के प्रकार, यानी बाईपास, एक्सप्रेसवे या फ्लाईओवर आदि के आधार पर उपयोगकर्ता शुल्क की गणना करेगा।

**डेडिकेटेड लेन**

शुरुआत में, मौजूदा टोल प्लाजा में डेडिकेटेड GNSS लेन होंगी, जिनमें आमतौर पर खुले गेट होंगे। ताकि GNSS-OBU लगे वाहनों को बिना रुके गुजरने दिया जा सके। इन लेन में ऐसे वाहनों को ट्रैक करने की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होगी, जिससे उन्हें बिना रुके गुजरने की अनुमति मिलेगी। धीरे-धीरे, इस प्रणाली के तहत और ज्यादा लेन लाई जाएंगी।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अगले दो महीनों में बोली दस्तावेज जारी करेगा। इसका लक्ष्य अप्रैल-जून 2025 तक वाणिज्यिक उपग्रह-आधारित टोलिंग के तहत पहला खंड चालू करना है।

TCS, Infosys, Accenture, RailTel, TCIL, Sky Toll, Kapsch, BEMobile

## सैटेलाइट के जरिए ऐसे कटेगा टोल टैक्स

और Movyon सहित भारतीय और वैश्विक प्रयोगिकी प्रमुखों ने GNSS-आधारित टोलिंग के लिए प्रणाली विकसित करने में दिलचस्पी जताई है और आवेदन दिए हैं।

**ट्रकों से होगी शुरुआत**  
GNSS-आधारित टोलिंग सिस्टम ट्रकों, बसों और खतरनाक सामान ले जाने वाले वाहनों से शुरू होगा। क्योंकि इनमें पहले से ही वाहन स्थान ट्रैकिंग (VLT) सिस्टम है और इसमें गोपनीयता के मुद्दे शामिल नहीं हैं।

नई प्रणाली में शामिल अगला खंड अन्य वाणिज्यिक वाहन होंगे। 2026-27 में आखिरी चरण के हिस्से के रूप में निजी वाहनों को GNSS ट्रैकिंग के तहत लाया जाएगा।

**जियो-फेंसिंग का काम पूरा**

राष्ट्रीय राजमार्ग की लगभग पूरी लंबाई की जियो-फेंसिंग पूरी हो चुकी है। टोल गणना के लिए सटीक प्रवेश और निकास बिंदुओं को चिह्नित करने के लिए जियो-फेंसिंग महत्वपूर्ण है।

GNSS टोलिंग एजेंसी जोएनएसएस-आधारित टोलिंग शुरू करने से पहले राजमार्गों की जियो-रेकॉर्डिंग करेगी।

**टोल कलेक्शन का लक्ष्य**

भारत में लगभग 1.4 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है, जिसमें से लगभग 45,000 किलोमीटर पर उपयोगकर्ता शुल्क वसूला जाता है।

शुरुआत में, जून 2025 तक 2,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों पर जोएनएसएस-आधारित टोलिंग शुरू की जाएगी। इसे नौ महीनों में 10,000 किलोमीटर, 15 महीनों में 25,000 किलोमीटर और दो साल में 50,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा।



## माँ झण्डेवाली सेवा समिति (रजि.), करनाल

वर्ष 2009 से सेवारत



पुण्यपार मीठा मनीषी पद्मपतेकर स्वामी ज्ञानानन्द जी महाराज

पुण्य संतों के पावन आशीर्वाद एवं सान्निध्य में  
**माँ झण्डेवाली सेवा समिति (रजि.), करनाल**  
वर्ष 2009 से सेवारत  
नवरात्रों के पावन अवसर पर प्रतिदिन



स्वामी दिव्यानन्द जी योगीराज

## माँ झण्डेवाली की चौकी

3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2024 रात्रि 8.00 बजे से 11.30 बजे तक  
आयोजन स्थल : श्री सनातन धर्म मन्दिर, कुंजपुरा रोड, करनाल

मंगलवार, 1 अक्टूबर 2024  
सायं 3.00 बजे से

**भव्य शोभा यात्रा**  
श्री सेवा समिति आश्रम से श्री सनातन धर्म मन्दिर

बुधवार, 2 अक्टूबर 2024  
सायं 7.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक

**मेंहदी माँ के नाम की**

शुक्रवार, 11 अक्टूबर 2024  
रात्रि 8.00 बजे

**कंजक पूजन एवं विशाल भण्डारा**

AMRITHARA Hospital

आयोजन स्थल पर प्रतिदिन निःशुल्क शुगर, वी.पी. की जांच एवं जनरल दवाईयों

आप इस पावन पर्व पर परिवार व इष्ट मित्रों सहित सादर आमंत्रित हैं।

मुख्य सेवादार कमल मुजाल 8950042345

सचिव सेवादार महेश गुलाटी 9254621635

कोष सेवादार प्रवीण वर्मा 9416032011

महिला संयोजिका इशा बठ्ठा 9812311973

सह-संयोजिका आशा अरोड़ा 9253725417

सह-संयोजिका संगीता शर्मा 7015220286

समस्त सेवादार माँ झण्डेवाली सेवा समिति (रजि.), करनाल

Bank : Punjab National Bank A/c No. 00362151012463 IFSC : PUNB0003610

## ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर अब नहीं रहेगी गंदगी, चलेगा विशेष सफाई अभियान

हर साल 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। इसी को देखते हर साल रेलवे भी स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाता है। इस बार भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिसके तहत ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को गंदगी नहीं मिलेगी। यह अभियान शनिवार से ही शुरू किया जाएगा। पहिए इस बार की स्वच्छता की क्या है थीम।

नई दिल्ली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष रेलवे स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाता है। इस बार यह विशेष स्वच्छता अभियान 14 सितंबर से शुरू होकर एक अक्टूबर तक चलेगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान का इस बार का थीम स्वभाव स्वच्छता- संस्कार स्वच्छता रखा गया है। दो अक्टूबर को गांधी जयंती 'स्वच्छ भारत दिवस' के रूप में मनाया जाएगा।

'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के अंतर्गत उत्तर रेलवे के मंडलों, कारखानों, एवं अन्य इकाइयों में

कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। रेलवे स्टेशनों, कार्यालयों, रेलवे कालोनियों, स्वास्थ्य इकाइयों एवं रेलवे ट्रैक में श्रमदान को चिह्नित करके गहन स्वच्छता अभियान चलाया जायेगा।

गांवों में लगाई जाएगी स्वच्छता चौपाल रेलवे स्टेशनों के आसपास स्थित गांवों में स्वच्छता चौपाल लगाई जाएगी, जिसके द्वारा गांववासियों को ट्रेनों, रेलवे स्टेशनों और रेल परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक किया जाएगा। इस स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत



सफाई कर्मचारियों और उनके परिवारों के हित के लिए स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

मेराथन, साइक्लोथन, खेल प्रतियोगिताओं तथा वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया जाएगा। रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल गतिविधियों व कचरे से कलाकृत बनाने तथा रिसाइकल उत्पादों की बिक्री पर विशेष बल दिया जाएगा। स्टेशनों पर सेल्फ़ी पाईंट स्थापित किए जाएंगे।

यात्रियों एवं कर्मचारियों को स्वच्छता के प्रति किया जाएगा जागरूक

यात्रियों एवं कर्मचारियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। रेलवे स्टेशनों तथा अन्य रेलवे परिसर पर शुच्य अपशिष्ट पहल जैसी घटनाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हाइलाइट और साझा किया जाएगा।

युवाओं में जागरूकता फैलाने के लिए कविता, निबंध, पोर्टिंग और पोस्टर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। शैक्षणिक संस्थान/स्कूल/आंगनवाड़ी केंद्र, इत्यादि में नारा लेखन, प्रश्नोत्तरी और जिंगल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।

**टैपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)**

**TOLWA**

website : www.tolwa.in  
Email : tolwadelhi@gmail.com  
bathlasyjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063  
कॉर्पोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली 110042

## वोकल फॉर लोकल सेफ्टी: आपकी भागीदारी से ही बदलाव संभव

डॉ. अंकुर शरण

आपका शहर डूब रहा है, और केवल शहर ही नहीं, हमारे पैसे और संसाधन भी पानी में बह रहे हैं। यह सिर्फ जलभराव की समस्या नहीं है, बल्कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी का सवाल भी है। अगर हम हर दिन नहीं तो हफ्ते में कम से कम एक घंटा अपने शहर, समाज और सड़कों की सुरक्षा के लिए दें, तो न केवल हमें बदलाव दिखाई देगा बल्कि हमारे आसपास का माहौल भी बेहतर होगा।

हम अपने शहरों में नई रेल लाइनें और बड़े बाजार बनाने पर जोर देते हैं, लेकिन अपने आस-पड़ोस की सफाई, सड़क सुरक्षा और पार्कों के रखरखाव पर ध्यान नहीं देते। यदि हमारे युवा जितनी मेहनत जिनमें करते हैं, उतनी मेहनत अपने समाज के पार्कों में लगाएं, तो वे भी सुंदर हो सकते हैं। हमारे पार्क और सार्वजनिक स्थान केवल इसलिए खराब हो रहे हैं क्योंकि अच्छे लोगों ने बोलना बंद कर दिया है, और कुछ गलत लोग अपनी मनमानी करने लगे हैं।

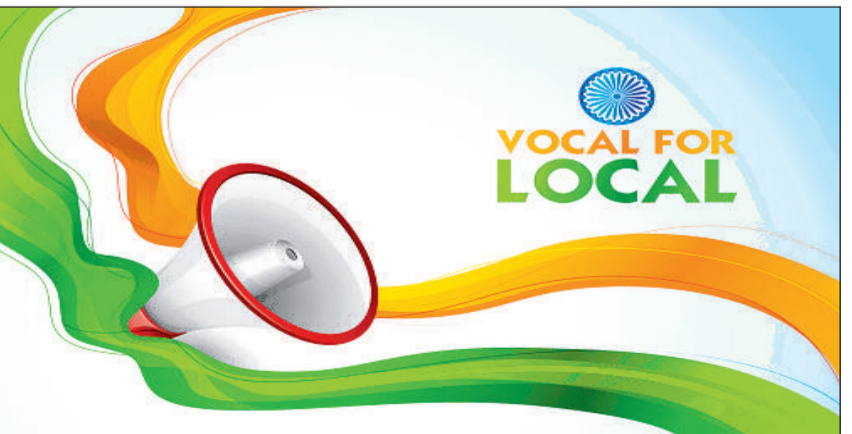
यहां बात बहस या लड़ाई-झगड़े की नहीं है, बल्कि सही समय पर सही बात कहने की है। यदि आपके सामने, आपकी सोसाइटी या शहर में कुछ गलत घट रहा है, तो यह केवल शासन-प्रशासन का काम नहीं है। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझे और कुछ समय सामाजिक सेवा में अवश्य निकाले। इससे न केवल आपके शहर और समाज में



सुधार होगा, बल्कि आपको आत्मसंतुष्टि भी मिलेगी। जब आप अपने आस-पड़ोस की सफाई और सुरक्षा के लिए काम करते हैं, तो आप अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बनते हैं। आप जो बदलाव लाते हैं, वह न केवल आपको पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा।

इसलिए, 'वोकल फॉर लोकल सेफ्टी' का समर्थन करें। अपने शहर की सुरक्षा, सफाई और सुन्दरता को बनाए रखने में हिस्सा लें। जब हर नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, तभी एक सशक्त, सुरक्षित और स्वच्छ समाज का निर्माण संभव हो सकेगा।

आज से शुरुआत करें: आवाज उठाएं,



कदम बढ़ाएं

अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है, तो चुप बैठने से कुछ नहीं बदलेगा। आवाज उठाएं, सोशल मीडिया पर लिखें, ट्वीट करें संबंधित अधिकारियों को, और तब तक फॉलो अप करते रहें जब तक आपकी सही जवाब और कार्रवाई न मिले। यह जरूरी है कि हम सिर्फ आलोचना न करें, बल्कि जब कुछ अच्छा हो रहा हो, तो उसे सराहें और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें।

राजनीतिक ज्ञान की बातें छोड़ें और उस ज्ञान का उपयोग करें जो आपके पास है। सोचें कि आप अपने शहर और समाज के लिए क्या कर सकते हैं, और फिर उसे करने में जुट जाएं। जो संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं, उन्हीं से शुरुआत करें।

कल का किसे पता ? जो आज आपके पास है, वही सबसे बड़ा साधन है।

बैठकर केवल देखने से कुछ नहीं होता, आपको उठकर कुछ करना होगा। और अगर आप असफल होते हैं, तो अपने तरीकों को बदलें, लेकिन हिम्मत कभी मत हारें। जैसे पेड़ों पर पत्ते बदलते हैं, लेकिन जड़ें और शाखाएं हमेशा मजबूती से खड़ी रहती हैं। हमें भी अपनी जड़ों और इरादों को मजबूत रखना है, चाहे रास्ते कितने भी कठिन क्यों न हों।

तो आइए, आज से ही शुरुआत करें। सिर्फ देखने और आलोचना करने के बजाय, कुछ करके दिखाएं। आपके छोटे-छोटे प्रयास ही बड़े बदलाव की नींव रख सकते हैं।

आइए, मिलकर इस बदलाव की शुरुआत करें।





## आयटम बुक करके डिलीवरी से पहले ही दिखाते थे रिटर्न, मनी रिफंड का पूरा खेल जान पुलिसवाले भी चकराए

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद से एक हेरान करने वाला मामला सामने आया है। फिलपकार्ट से लाखों का रिफंड लेकर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। आरोपितों ने डिलीवरी से पहले ही डेटाबेस में हेरफेर कर माल को रिटर्न दिखाया और रिफंड प्राप्त कर लिया। कंपनी के दो पूर्व कर्मचारियों की आईडी का भी इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

**गाजियाबाद।** ई-कामर्स कंपनी फिलपकार्ट से कई शहरों के लिए महंगे माल का ऑर्डर देकर फर्जीवाड़ा कर लाखों का रिफंड लेने का मामला सामने आया है।

आरोपितों ने डिलीवरी हब कर्मचारियों की आईडी का प्रयोग कर माल दिए गए पते पर डिलीवर होने से पहले ही डेटाबेस में हेरफेर कर डिलीवर दिखा दिया।

फिर माल को रिटर्न दिखाकर रिफंड प्रोसेस पूरा किया और खाते में रिटर्न भुगतान भी प्राप्त कर लिया। जबकि वास्तविकता में माल बुक होने के बाद रास्ते में ही था।

**स्मार्टवाच जैसे महंगे आइटम करते थे बुक**

कंपनी की जांच में सामने आया है कि स्मार्टवाच और महंगे पेन की बुकिंग फर्जी नाम-पते पर खोले गए खाते से की गई है। हर ऑर्डर में केश ऑन डिलीवरी का विकल्प भुगतान के लिए चुना गया।

माल डिलीवर करने वाली कंपनी ई-कार्ट ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराकर



आरोपित बुक करने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि जिस बैंक खाते में रिफंड लिया गया है उसकी जानकारी जुटाकर शीघ्र आरोपितों को पकड़ा जाएगा।

डीपीएस मेरठ रोड के पास ई-कार्ट कंपनी का डिलीवरी हब है। यह कंपनी फिलपकार्ट की सहयोगी कंपनी है जो उसके लिए माल की डिलीवरी कई शहरों में बने हब के जरिए करती है।

**गाजियाबाद में एक ऑर्डर बुक होने पर हुआ खुलासा**

कंपनी के प्रवर्तन अधिकारी रितिन दीप के मुताबिक बीते दिनों गाजियाबाद में एक स्मार्टवाच की बुकिंग के बाद पैकेट डिलीवरी हब

**हर बार बैंक खाता और मोबाइल नंबर नया**

कंपनी अधिकारी रितिन दीप का कहना है कि जांच में सामने आया है कि आरोपितों ने प्रत्येक बार माल की बुकिंग के लिए फिलपकार्ट पर नए मोबाइल नंबर से फर्जी नाम और पते पर आईडी बनाई। लेकिन रिफंड के लिए बंधन बैंक के एक खाते का प्रयोग कर धनराशि वापस ली गई है।

गाजियाबाद के साथ ही बंगलुरु, मुंबई, जयपुर, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, सूरत, अहमदाबाद, लखनऊ, मेरठ, चंडीगढ़ समेत देश के 55 शहरों के लिए माल की बुकिंग कराई गई।

रितिन दीप के मुताबिक केश ऑन डिलीवरी विकल्प चुनने पर ग्राहक को माल की डिलीवरी के समय भुगतान करना होता है। ऐसे में मामले में यदि उत्पाद वापस होता है तब कंपनी पहले पैकेट वापस लेती है। उसके बाद ग्राहक के दर्ज कराए गए बैंक खाते में रिफंड धनराशि क्रेडिट कर देती है।

**कंपनी के दो पूर्व कर्मचारियों की आईडी का भी प्रयोग किया**

जांच में सामने आया है कि पूरे फर्जीवाड़े में कंपनी के दो पूर्व कर्मचारी राहुल और सुमित चौहान समेत मौजूदा कर्मचारी कामिनी की आईडी का प्रयोग किया गया है। राहुल और सुमित चौहान की आईडी सिस्टम में बंद नहीं हुई हैं। इसलिए उनकी आईडी के जरिए भी डेटाबेस में फर्जीवाड़ा संभव हुआ।

## टॉयलेट के लिए रोका कैंटर, पीछे से ट्रक ने मारी टक्कर; दो की मौत



गुरुग्राम शहर के केएमपी पर खड़े कैंटर में ट्रक की टक्कर लगने से चालक समेत दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की शिकायत में बताया गया कि कैंटर में कुंडली से कॉपर लोड कर उसे गुजरात ले जाना था। तभी रास्ते में फरुखनगर के पास लघुशंका करने के लिए कैंटर को रोका गया। तभी यह हादसा हुआ।

**गुरुग्राम।** गुरुग्राम के केएमपी पर खड़े कैंटर में पीछे से तेज रफ्तार आए ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में कैंटर चालक समेत दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर जांच शुरू कर दी है।

**पुलिस को दी शिकायत में कही ये बात**  
राजस्थान के कोटपुतली निवासी कुशेश ने थाना

पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह 11 सितंबर को अपने चचेरे भाई अतुल कुमार के साथ कैंटर से सोनीपत के कुंडली गए थे। इसमें कोटपुतली के पिंटू भी थे। अतुल कैंटर चालक थे।

**ट्रक ने कैंटर में जोरदार मारी टक्कर**

कैंटर में कुंडली से कॉपर लोड कर गुजरात की तरफ ले जाना था। गुरुवार रात दो बजे गुजरात की तरफ जाते समय केएमपी पर फरुखनगर के पास अतुल ने लघुशंका करने के लिए कैंटर रोका। इसी दौरान अंधेरा होने के कारण पीछे से तेज रफ्तार आ रहे ट्रक ने कैंटर में जोरदार टक्कर मार दी।

हादसे में अतुल कुमार और पिंटू को गंभीर चोटें लगीं। इन्हें अस्पताल ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक को मोके पर ही छोड़कर फरार हो गया।

## नोएडा DM के 'एक्स' अकाउंट से राहुल गांधी पर की गई अभद्र टिप्पणी, केस दर्ज; विवाद के बीच IAS ने बताई वजह

नोएडा के जिलाधिकारी के एक्स हैंडल से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी की गई है। इस मामले में प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करा दी है और साइबर सेल जांच में जुट गई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने एक्स हैंडल पर प्रधानमंत्री को लेकर टिप्पणी की थी जिसके बाद जिलाधिकारी की एक्स आईडी से श्रीनेत और राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई।

**मेरठ नोएडा।** गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी के एक्स हैंडल का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस नेता व सदन में नेता प्रतिपक्ष को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी से बवाल मच गया है। प्रशासन की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है। साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी है।

**नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी**

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने एक्स हैंडल पर प्रधानमंत्री को लेकर टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी पर गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी की एक्स आईडी से सुप्रिया श्रीनेत व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई।

**जिलाधिकारी ने दर्ज कराई शिकायत**  
श्रीनेत ने एक्स पर आपत्ति जताई। इसके बाद



बवाल मच गया। आनन-फानन में जिला प्रशासन सक्रिय हो गया और एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिलाधिकारी के एक्स हैंडल से जानकारी दी गई कि किसी असाामाजिक तत्व द्वारा एक्स आईडी का दुरुपयोग करते हुए गलत टिप्पणी की गई है, जिसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज कराई गई है। साइबर सेल द्वारा जांच शुरू कर दी गई है।

## 'टॉयलेट करने की जगह नहीं थी', जूस में पेशाब मिलाकर बेचने वाले आरोपी का पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला बयान

लोनी में जूस में पेशाब मिलाकर बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इंद्रापुरी कॉलोनी में खुशी जूस कॉर्नर नाम की दुकान पर यह घटना हुई। कुछ लोगों ने दुकानदार और उसके नाबालिग कर्मचारी को बोलत में पेशाब ले जाते देखा और हंगामा कर दिया। पुलिस ने मौके से बोलत में पेशाब बरामद किया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

**लोनी।** लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की इंद्रापुरी कॉलोनी में शुक्रवार शाम को एक ऐसी खबर सामने आई जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

दो दिन पहले ही गाजियाबाद की एक मशहूर मिठाई की दुकान के समोसे में मेंढक की टांग मिलने की घटना सामने आने के बाद एक जूस की दुकान पर पेशाब मिलाकर बेचने का आरोप सामने आया है।

आइए जानते हैं कि इस पूरी घटना का खुलासा कैसे हुआ और जूस में पेशाब



मिलाने का काम कब से चल रहा था, इसे लेकर पुलिस ने क्या बताया है। पुलिस इस मामले में नाबालिग समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

**क्या है पूरा मामला**

जानकारी के अनुसार, लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की इंद्रापुरी कॉलोनी में खुशी जूस कॉर्नर के नाम से एक दुकान है। वहां शुक्रवार शाम देखते-देखते भीड़ जुट गई।

दावा है कि कुछ लोगों ने जूस कॉर्नर में काम करने वाले लड़कों को एक बोलत में पेशाब ले जाते देख लिया। उन्होंने दुकानदार और उसके नाबालिग कर्मचारी पर जूस में पेशाब मिलाकर बेचने का आरोप लगाया। इससे लोगों में भारी रोष हो गया। लोगों ने हंगामा कर दोनों को दबोच लिया। सूचना लोनी बॉर्डर थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची लोनी पुलिस ने दुकान से बोलत में

पेशाब बरामद कर लिया।

**आरोपियों ने क्या कहा**

पुलिस ने नाबालिग समेत दोनों को पकड़ लिया। पुलिस की ओर से मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि दुकान में व आसपास पेशाब करने के लिए जगह नहीं थी। उन्हें दूर जाना पड़ता था।

इसलिए वह बोलत में पेशाब करते थे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर

तेजी से वायरल हो रहा है। लोग आरोपितों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

**एक महीने से दुकान चला रहा था आरोपी**

पुलिस पूछताछ में दुकानदार ने बताया कि वह मूलरूप से बहराइच के कैसरगंज के रहने वाले हैं। यह दुकान उनके चचेरे भाई की थी। वह एक माह पूर्व अपने घर चले गए। तभी से वह दोनों इस दुकान को चला रहे हैं।

दुकान में कोई सीसीटीवी कैमरा भी पुलिस जांच में लगा नहीं मिला है। घटना के बाद से लोगों में गुस्सा है। उन्होंने क्षेत्र में चल रही कई अन्य दुकानों की भी जांच कराने की मांग की है।

**पुलिस को सूचना मिली थी कि खुशी**

जूस कॉर्नर पर जूस में पेशाब मिलाया जाता है। मौके पर तलाशी के दौरान एक कैम से पेशाब बरामद हुआ है। पुलिस से आभिर व उसके बाल अपचारी साथी को पकड़ लिया है। पुलिस की ओर से रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। -**राजेश वर्मा, सहायक पुलिस आयुक्त, अंकुर विहार।**

## विज्ञान और कानून की भी भाषा बने हिंदी

विजय गर्ग

पिछले 75 वर्षों में हिंदी को राजभाषा के रूप में पूरी तरह स्थापित करने में कई चुनौतियां सामने आईं। सबसे बड़ी चुनौती भाषाई विविधता है। भारत जैसे बहुभाषी देश में जहां विभिन्न राज्यों की अपनी-अपनी भाषाएं हैं वहां एक भाषा को पूरे देश में लागू करना जटिल कार्य है किंतु आज के समय में डिजिटल क्रांति के साथ हिंदी को एक नया मंच मिला है। जब 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। यह निर्णय स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण था, जहां भाषा की विविधता के बावजूद एक ऐसी भाषा को राजभाषा चुना गया, जो देश के अधिकांश लोगों के लिए सहज और सुलभ हो। तबसे हिंदी ने अपनी भूमिका में अनेक परिवर्तन देखे हैं और देश की प्रमुख भाषाओं में से एक बनी हुई है।

पिछले 75 वर्षों में हिंदी ने न केवल एक भाषा के रूप में, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह वह भाषा है, जिसने देश के आत्मा को प्रतिबिंबित किया है और स्वतंत्रता के बाद के भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक एकाता को सुदृढ़ किया है। तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति के साथ हिंदी ने परंपरा और आधुनिकता के बीच एक पुल का काम किया है। आज हिंदी ने न केवल भारत, बल्कि कई देशों में भी पढ़ाई और बोली जाती है। हालांकि हिंदी ने एक लंबी यात्रा तय की है, लेकिन इसके सामने आज भी कई चुनौतियां हैं। भाषाई विविधता वाले देश में सभी भाषाओं को सम्मान और महत्व देना आवश्यक है। हिंदी को बढ़ावा देने के साथ-साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को भी सहजने और संरक्षित करने की जिम्मेदारी है।

पिछले 75 वर्षों में हिंदी को राजभाषा के रूप में पूरी तरह स्थापित करने में कई चुनौतियां सामने आईं। सबसे बड़ी चुनौती भाषाई विविधता है। भारत जैसे बहुभाषी देश में जहां विभिन्न राज्यों की अपनी-अपनी भाषाएं हैं, वहां एक भाषा को पूरे देश में लागू करना जटिल कार्य है, किंतु आज के समय में डिजिटल क्रांति के साथ हिंदी को एक नया मंच मिला है। इंटरनेट ने हिंदी को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। यूवा पीढ़ी हिंदी का उपयोग डिजिटल



माध्यमों में कर रही है, जिससे यह भाषा और अधिक सशक्त हो रही है। तकनीकी क्षेत्र में भी हिंदी का उपयोग बढ़ रहा है। इन 75 वर्षों में हिंदी को कानून की भाषा बनाना एक महत्वपूर्ण, लेकिन चुनौतीपूर्ण प्रश्न रहा है। इसके लिए संवैधानिक, कानूनी, प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर व्यापक बदलाव की आवश्यकता होगी। यदि इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाते हैं, तो यह भारतीय न्यायिक प्रणाली को अधिक सुलभ और पारदर्शी बना सकता है। इससे न केवल हिंदी भाषी जनता को लाभ होगा, बल्कि यह लोकतंत्र को भी सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। हिंदी को कानून की भाषा बनाने के लिए कानूनी शिक्षा प्रणाली में भी बदलाव आवश्यक होगा। वर्तमान में अधिकांश कानूनी पाठ्यक्रम और पुस्तकों का माध्यम

अंग्रेजी है। हिंदी में कानूनी साहित्य, पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास करना होगा। इसके साथ ही वकीलों, न्यायाधीशों और अन्य कानूनी पेशेवरों को हिंदी में दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण लेना होगा। विज्ञान और तकनीक के युग में भाषा का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। आज ज्ञान का सुजन और प्रसार विज्ञान और तकनीक के माध्यम से ही हो रहा है। इन दोनों ही क्षेत्रों में अंग्रेजी का वर्चस्व है। भारत जैसे बहुभाषी देश में जब एक बड़ी जनसंख्या हिंदी में संवाद करती है, तो यह आवश्यक हो जाता है कि विज्ञान और तकनीक से संबंधित ज्ञान भी इसी भाषा में उपलब्ध हो। हिंदी को विज्ञान की समृद्ध भाषा बनाना आवश्यक है, क्योंकि यह समाज के समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। इससे न केवल भाषा का विकास होगा, बल्कि आम

जनता को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। प्रौद्योगिकी हिंदी को विज्ञान और साथ ही तकनीक की उन्नत भाषा बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। डिजिटल मीडिया के माध्यम से हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी सामग्री को व्यापक रूप से प्रसारित किया जा सकता है। अनुवाद साफ्टवेयर और भाषा पहचान तकनीक भी इस दिशा में मददगार साबित हो रहे हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से भाषाई बाधाओं को दूर किया जा सकता है और जटिल तकनीकी सामग्री को हिंदी में सुलभ बनाया जा सकता है।

हिंदी विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भारत के अलावा नेपाल, फिजी, मारीशस, गुयाना और त्रिनिदाद आदि देशों में भी इसका प्रयोग होता है, लेकिन भारत की राजभाषा घोषित होने के 75 साल बाद भी हिंदी अभी तक संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं बन पाई है। हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के लिए भारत को अन्य देशों से सहयोग और समर्थन प्राप्त करना होगा, विशेषकर उन देशों से जहां हिंदी का उपयोग होता है। हाल के वर्षों में भारत सरकार ने हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्रालय ने कई बार इस मुद्दे को उठाया और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया। भविष्य में हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाने के लिए भारत को और भी कूटनीतिक प्रयास करने होंगे। इसके लिए वित्तीय सहयोग के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय समर्थन भी आवश्यक है। यदि भारत अन्य हिंदी भाषी देशों और वैश्विक शक्तियों का समर्थन जुटा पाने में सफल होता है तो यह संभव है कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में स्थान मिल सके।

हिंदी को राजभाषा के रूप में पूरी तरह स्थापित करने में अभी भी कई चुनौतियां हैं, लेकिन यह निश्चित है कि हिंदी अपने सशक्त साहित्य, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और बढ़ते डिजिटल माध्यमों के साथ भविष्य में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

**सेवानिवृत्त प्रिंसिपल एजुकेशनल स्ट्रीट कौबर चंद एमएचआर मल्लोट - 152107 पंजाब**

## यीडा की 361 आवासीय भूखंड योजना पर आया अपडेट, ड्रॉ में इन लोगों का नाम आने की संभावना अधिक

यमुना प्राधिकरण ने आवासीय भूखंड योजना का ड्रा निकालने के लिए कार्यक्रम की जगह तय कर ली है। बता दें इंडिया एक्सपो मार्ट में आगामी 10 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से ड्रा प्रक्रिया शुरू होगी। योजना के तहत दो लाख से ज्यादा लोगों ने घर के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। गौरतलब है कि यमुना प्राधिकरण ने 361 आवासीय भूखंडों की योजना निकाली थी।

**मेरठ नोएडा।** यमुना प्राधिकरण ने आवासीय भूखंड योजना का ड्रा करने के लिए इंडिया एक्सपो मार्ट को चुना है। 10 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से ड्रा प्रक्रिया शुरू होकर अंतिम भूखंड के आवंटन तक जारी रहेगी। आवेदकों की अधिक संख्या को देखते हुए प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है।

ड्रा प्रक्रिया की निगरानी के लिए नियुक्त जूरी में हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अतिरिक्त दो सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी होंगे। तैयारी के लिए होकर अंतिम की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति गठित की गई है।

**यीडा से निकाली थी 361 आवासीय भूखंड योजना**

यमुना प्राधिकरण ने पांच जुलाई को 361 आवासीय भूखंडों की योजना निकाली थी। योजना में अब तक के सबसे अधिक 2,02,822 आवेदन मिले हैं। प्रक्रिया की पारदर्शिता कायम रखने के लिए दूरदर्शन पर इसके सीधे प्रसारण के प्रयास किए जा रहे हैं।



इसके अतिरिक्त इंटरनेट मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी इसका सजीव प्रसारण होगा। सीईओ डा. अरुणवीर सिंह ने दावा किया है कि ड्रा प्रक्रिया संपन्न होने के 72 घंटों के अंदर असफल आवेदकों की पंजीकरण राशि उनके खाते में लौटा दी जाएगी।

ड्रा में शामिल होने के लिए आवेदकों की पात्रता की जानकारी के लिए उनकी सूची प्राधिकरण की वेबसाइट पर जल्द अपलोड की जाएगी। आवेदन अपनी आवेदन संख्या के जरिये जान सकेंगे कि उन्हें ड्रा में शामिल होने का मौका मिलेगा या नहीं।

**एक मुश्त भुगतान वालों को ही ड्रा में शामिल होने का मिलेगा मौका**

योजना में 361 भूखंडों के सापेक्ष मिले आवेदन में एक मुश्त भुगतान काफ़ी अधिक है। इसलिए ड्रा में उन्हें ही शामिल होने का मौका मिलेगा। किस्तों में भुगतान का विकल्प चुनने वालों को ड्रा में शामिल होने की संभावना लगभग नहीं है।

- सौजन्य :-

ईवी ड्राइव द फ्यूचर



## टाटा पंच को मिलेंगे शानदार नए फीचर्स; पहले से ज्यादा हो जाएगी लजरी

परिवहन विशेष न्यूज

टाटा मोटर्स अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी में से एक Tata Punch के अपडेटेड मॉडल को लाने की तैयारी कर रही है। हाल ही में इसके टेरिफिंग मॉडल को सॉफ्ट किया गया है। वहीं इसका एक ग्लोशर सामने आया है जिसमें इसके कई वैरिएंट को नए फीचर्स मिलने की बात सामने आई है। आइए जानते हैं कि Tata Punch के किस वैरिएंट में क्या फीचर्स मिलेंगे।

**नई दिल्ली।** टाटा पंच का नया ग्लोशर सामने आया है, जिसमें यह पता चल रहा है कि कंपनी इसे नए फीचर्स मिलने वाले है। वहीं, यह टाटा की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी में से एक है। जिसे देखते हुए कंपनी इसे लगातार अपडेट

करके ज्यादा बेहतर करती जा रही है। हम यहां पर आपको नई Tata Punch किन फीचर्स के साथ आएगी, बता रहे हैं। आइए जानते हैं।

**2024 Tata Punch: प्योर वैरिएंट**  
इसके प्योर वैरिएंट में डुअल एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), रियर पार्किंग सेंसर, ISOFIX चाइल्ड सीट प्रोविजन, चार्बी के साथ सेंट्रल लॉकिंग, फ्रंट पावर विंडो, टिल्ट स्टीयरिंग, 90-डिग्री डोर ओपनिंग, रियर फ्लैट फ्लोर, ORVM पर LED इंडिकेटर, ब्लैक ODH और ORVM, 4-इंच डिजिटल क्लस्टर, डोर-व्हील आर्क और सिल क्लैडिंग, आइडल स्टार्ट स्टॉप (ISS) तकनीक (पेट्रोल) जैसे फीचर्स मिलेंगे।

**2024 Tata Punch: प्योर (O) वैरिएंट**

टाटा पंच के इस वैरिएंट में प्योर के सभी फीचर्स मिलेंगे। इसके साथ ही यह फिलप की के साथ सेंट्रल रिमोट लॉकिंग, इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ ORVM, फुल व्हील कवर जैसे फीचर्स के साथ आएगी।

**2024 Tata Punch: एडवेंचर वैरिएंट**  
इसमें भी टाटा पंच प्योर वैरिएंट वाले सभी फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा यह फ्लोटिंग 8.89 cm इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4 स्पीकर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, सभी पावर विंडो, फिलप की के साथ सेंट्रल रिमोट लॉकिंग, एंटी-ग्लेयर IRVM, USB चार्जिंग पोर्ट, इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ ORVM, पार्सल ट्रे, फॉलो-मी-होम हेडलैप, फुल व्हील कवर, बॉडी-कलर्ड ORVM और ODH जैसे फीचर्स के साथ आएगी।

**2024 Tata Punch: एडवेंचर रिदम वैरिएंट**  
टाटा पंच एडवेंचर रिदम वैरिएंट में एडवेंचर के सभी फीचर्स मिलेंगे। इसके साथ यह फ्लोटिंग 17.78 सेमी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, 2 टीवीटर, वायर्ड इंटीग्रेड ऑटो और रेपल कारपेल, रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स से लैस होगी।

**2024 Tata Punch: एडवेंचर सनरूप वैरिएंट**  
टाटा पंच के इस वैरिएंट में भी एडवेंचर वाले सभी फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा, इसमें इलेक्ट्रिकल सनरूप, आर्मरिस्ट के साथ ग्रैंड कंसोल, रियर एसी वेंट, ऑटो हेडलैप, रेन-सेंसिंग वाइपर, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, रूफ रेल, शार्क फिन एंटीना, रियर ए-टाइप यूएसबी पोर्ट जैसे फीचर्स मिलेंगे।

## ईवी, हाइब्रिड, प्लग-इन-हाइब्रिड भारत के स्वच्छ ऊर्जा ऑटो क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे: रिपोर्ट

परिवहन विशेष न्यूज

एलाय सिक्वोरिटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र का ईवी की ओर रुख केवल इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही निर्भर नहीं होगा बल्कि इसमें हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड भी शामिल होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों, हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड का संयोजन देश को केवल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर निर्भर रहने के बजाय स्वच्छ ऊर्जा समाधानों की ओर ले जाएगा।

रिपोर्ट के अनुसार भारतीय ईवी बाजार में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। 2023 में वैश्विक ईवी बिक्री 14 मिलियन तक पहुंच गई, जिसमें भारत में 90 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। 2030 तक भारत सरकार का लक्ष्य 30 प्रतिशत ईवी पैठ हासिल करना है, जिसमें विस्तारित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत बैटरी प्रबंधन प्रणाली और नए ईवी मॉडल जारी करने जैसे प्रमुख सक्षमकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के चीफ प्रोथ ऑफिसर गौरव गुप्ता के अनुसार अगले 5-6 सालों में लगभग 200,000 चार्जर की आवश्यकता होगी, जिसमें हर 50 वाहनों के लिए 1 चार्जर होगा। CY30 तक कनेक्टेड कार अपनाने की दर 75-80 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है और ADAS अपनाने की दर 45 प्रतिशत तक पहुंचनी चाहिए, जिससे बैटरी इलेक्ट्रिक व्हील अधिग्रहण अधिक आकर्षक हो जाएगा।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय



ऑटोमोटिव क्षेत्र के भविष्य को आकार देने वाले प्रमुख रुझानों में से एक सॉफ्टवेयर-परिभाषित वाहनों SDV का उदय है। ये वाहन इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर को एकीकृत सिस्टम में एकीकृत करने पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। इसमें कहा गया है कि ऐसे वाहन उन्नत सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करते हैं जिनका मुद्रिकरण किया जा सकता है, जिससे ओईएम को अपने व्यवसाय मॉडल को हार्डवेयर-केंद्रित से सॉफ्टवेयर और स्मार्ट

समाधान-संचालित संचालन में बदलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

ऑटोमोबिलिटी के पार्टनर और सह-संस्थापक बेविन जैकब ने कहा कि ओईएम अत्याधुनिक तकनीक को शामिल करके और नाटकीय बदलाव के लिए तैयार है। स्वच्छ स्मार्ट समाधानों से मूल्य निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा, ऑन-डिमांड मोबिलिटी सेवाएं, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी, विद्युतीकरण, स्वायत्त ड्राइविंग और मोबिलिटी-एज-ए-सर्विस द्वारा संचालित हैं, उद्योग के भविष्य के

लिए एक परिवर्तनकारी विकास का प्रतिनिधित्व करती हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत का ऑटोमोटिव क्षेत्र तकनीकी प्रगति, सहयोगी प्रयासों और संभारणीय गतिशीलता की ओर एक मजबूत कदम से प्रेरित एक नाटकीय बदलाव के लिए तैयार है। स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन बहुआयामी होगा, जिसमें ईवी, हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड अग्रणी होंगे, जिन्हें स्थानीय उत्पादन और स्मार्ट समाधानों के एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा समर्थित किया जाएगा।

परिवहन विशेष न्यूज

यूरोपीय संघ (EU) (ईयू) चीन से आयात किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों पर निश्चित टैरिफ (शुल्क) लगाने के लिए 25 सितंबर को एक मतदान करने का लक्ष्य बना रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक योजना से परिचित लोगों ने यह जानकारी दी है।

मतदान नवंबर से शुरू लागू करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। जब तक कि एक योग्य बहुमत - यूरोपीय संघ की 65% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले 15 सदस्य देश - इस कदम का विरोध नहीं करते। नाम न बताने की शर्त पर मतदान की तारीख अभी भी बदल सकती है।

यूरोपीय संघ ने SAIC मोटर कॉर्प, Volvo Car AB (वोल्वो कार एबी) की मालिक Geely (गैली) और BYD (बीवाईडी) कंपनी पर क्रमशः 36.3%, 19.3% और 17% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है। जो चीन के निर्यातकों पर पहले से लागू 10% टैरिफ के अतिरिक्त है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इन दरों में थोड़ा संशोधन करके इसे कम किया जा

सकता है। टेस्ला इंक को बेस ड्यूटी के अलावा 8% से थोड़ी कम दर का अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने पिछले साल ईवी जांच शुरू की थी। जिसमें कहा गया था कि चीनी कंपनियों सरकारी सब्सिडी से अनुचित लाभ उठा रही हैं और यूरोप के बाजारों को अतिरिक्त उत्पादन से भर रहे हैं। इसके जवाब में, बीजिंग ने ब्रांडी, डेयरी और पोर्क उत्पादों के यूरोपीय संघ के निर्यात में एंटी-डॉपिंग जांच शुरू की।

चीन और यूरोपीय संघ टैरिफ के विकल्प तलाशने के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये बातचीत सफल नहीं हुई है। ब्रुसेल्स के लिए, किसी भी समाधान को विश्व व्यापार संगठन के नियमों के आधार पर होना चाहिए। और यूरोपीय संघ की जांच में पहचानी गई अंतर्निहित हानिकारक सब्सिडी को संबोधित करना चाहिए।

चर्चा अगले सप्ताह जारी रहेगी जब चीनी वाणिज्य मंत्री वांग वेनताओ यूरोपीय संघ के व्यापार प्रमुख वाल्डिस डोमोरोस्की से मिलने के लिए यूरोप का दौरा करेंगे।

चीन का दावा है कि ये उपाय संरक्षणवादी हैं और उसने कई क्षेत्रों

पर अपने शुल्क लगाकर जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी है। साथ ही वह सभी विवादों को एक पैकेज के रूप में हल करने के लिए एक समझौते की मांग कर रहा है। बीजिंग WTO में भी इन उपायों को चुनौती दे रहा है। लोगों ने कहा कि यूरोपीय संघ चीनी जांच को प्रतिशोध के रूप में देखता है और तीनों जांचों में अपने हितों की रक्षा करने का इरादा रखता है।

स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज ने इस सप्ताह की शुरुआत में चीन की यात्रा के दौरान यह कहकर लोगों को चौंका दिया था कि यूरोपीय संघ को टैरिफ लगाने की अपनी योजना पर फिर से विचार करना चाहिए। जर्मनी भी ब्रुसेल्स पर शुल्कों का विकल्प खोजने के लिए दबाव डाल रहा है। क्योंकि उसके ऑटो उद्योग ने इन उपायों के बारे में चिंता व्यक्त की है।

जर्मनी और स्पेन दोनों के पास एक दूसरे पर प्रतिबंधों के चक्र से बचने के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय प्रोत्साहन हैं। फॉक्सवैगन एजी और बीएमडब्ल्यू एजी सहित जर्मन वाहन निर्माता कंपनियों को व्यापार विवाद में सबसे ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि उन्होंने 2022 में सामूहिक रूप से वहां 4.6 मिलियन कारें बेचीं।

## शुरुआत करें आज से भविष्योन्मुखी व्यवसाय

परिवहन विशेष न्यूज

दुनिया तेजी से बदल रही है। इसके साथ ही लोगों की मांग भी बदल रही है। इसे पूरा करने के लिए कई नए बिजनेस मॉडल बाजार में आ रहे हैं। अगर आप भी किसी नए बिजनेस आइडिया की तलाश में हैं तो आज हम आपको ऐसे बिजनेस के बारे में बता रहे हैं जो पूरी तरह से भविष्य की मांग पर आधारित हैं। अगर आप इन भविष्योन्मुखी व्यवसाय को शुरू करते हैं तो आप न सिर्फ सफल होंगे बल्कि बंपर मुनाफा भी कमाएंगे।

माइक्रो मोबिलिटी: माइक्रो मोबिलिटी हम में से कई लोगों के लिए एक नया शब्द है। लेकिन यह बेस्ट प्यूचर बिजनेस आइडियाज में से एक है। माइक्रो मोबिलिटी का मतलब कम्प्यूटेशन के लिए कम गति से चलने वाले हल्के वाहनों का उपयोग करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रैफिक के कारण हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते यातायात के समाधानों में से एक माइक्रो मोबिलिटी है। माइक्रो मोबिलिटी में ई-बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटर, स्केटबोर्ड, इलेक्ट्रिकल पैडल साइकिल का इस्तेमाल किया जाता है। यह शहरी परिवहन का भविष्य है। माइक्रो मोबिलिटी से जुड़े बिजनेस के अवसर नीचे दिए गए हैं।

**माइक्रो मोबिलिटी रेंटल बिजनेस**  
सूक्ष्म गतिशीलता वाहन विकास और बिक्री  
माइक्रो-मोबिलिटी वाहन साझा करने के लिए ऐप और प्लेटफॉर्म विकास  
माइक्रो मोबिलिटी वाहन की जीपीएस आधारित ट्रैकिंग

इलेक्ट्रिक वाहन: इलेक्ट्रिक वाहन एक हकीकत बनने जा रही है। यह कई लोगों के लिए बिजनेस के नए विकल्प खोलेंगा। यह उम्मीद की जाती है कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल भविष्य का वाहन बन जाएगा। प्यूचर बिजनेस आइडियाज की रेश में आप इलेक्ट्रिक वाहन को भी गिन सकते हो, इसकी लोकप्रियता का मुख्य कारण इसका टिकाऊ होना और पर्यावरणीय स्थिरता है। इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च होने के बाद हमारे पास बिजनेस के कई नए मौके होंगे, जैसे -

इलेक्ट्रिक वाहन सर्विस गैरैज  
इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन सेटअप

स्पेयर पार्ट्स का निर्माण/बिक्री  
बैटरी स्वीप और स्क्रीपिंग

**ईवी चार्जिंग स्टेशन:** देश में इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटर और कारों की बिक्री लगातार बढ़ रही है। बाजार में बढ़ती मांग और बदलते ट्रेंड को देखते हुए ऑटो

### FUTURISTIC BUSINESS IDEAS



कंपनियों की ईवी पर अपना फोकस बढ़ा रही है। अब जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन बढ़ रहा है, तो इसे पूरा करने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। इस मौके का फायदा उठाते हुए आप चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अच्छी लोकेशन पर जगह की जरूरत होगी। कई कंपनियों चार्जिंग स्टेशन लगाने में मदद कर रही हैं। आप कंपनियों से गठजोड़ करके आसानी से यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इससे आने वाले समय में अच्छी कमाई होगी।

**वाहन धुलाई और सर्विसिंग का व्यवसाय:** आज हर गली-मोहल्ले में वाहनों की धुलाई और सर्विसिंग का व्यवसाय भी बहुत तेजी से चल रहा है। वर्तमान समय में जिस तरह से वाहनों का उपयोग हो रहा है, भविष्य में इसमें और भी बढ़ोतरी होगी। भविष्य में वाहनों का स्वरूप भी बदलेगा और गैस और अन्य सौएनजी के साथ-साथ ईंधन की जगह बायोप्यूल और इलेक्ट्रिक चार्जिंग का भी उपयोग किया जाएगा। इसके बारे में आपको और अधिक जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है, आपको इसकी तकनीक सीखने की जरूरत है। जब आप इसकी नई तकनीकों के बारे में जानेंगे, तो आप इसका व्यवसाय और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कार सर्विसिंग में केवल कार धोने से ही 200 से 300 रुपये की कमाई हो सकती है और अगर एक या दो नट बोल्ट भी टाइट करवाने पड़े, तो बिल और भी बढ़ जाता है। इसमें लागत कम और कमाई ज्यादा होती है, बस आपको इसके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए।

**सोलर पैनल बिजनेस:** जब बेस्ट बिजनेस आइडिया की बात आती है तो सोलर पैनल का जिक्र होना स्वाभाविक है। सोलर पैनल बिजनेस आज के दौर में बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि को कम करने के लिए और ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश में बिजली का संकट बढ़ता जा रहा है। जितनी बिजली की मांग है, उतनी बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है। ऐसे में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से

इन समस्याओं से निजात मिल सकती है। सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में यह बिजनेस काफी फायदेमंद है। आने वाले समय में सौर ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ेगी। जिस तरह से बिजली की कमी है, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, लोग सौर ऊर्जा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इस बिजनेस में जोखिम लगभग नहीं है और भविष्य में यह बिजनेस काफी बढ़ेगा। इसलिए इस बिजनेस को करके आप अपना खुद का एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस व्यवसाय में जोखिम न के बराबर है और भविष्य में यह व्यवसाय बहुत बढ़ेगा और जिस तरह से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, हर परिवार को बिजली उपलब्ध कराना सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में सोलर पैनल सबसे अहम भूमिका निभाएगा। अगर आप कोई बड़ा व्यवसाय करने के इच्छुक हैं तो सोलर पैनल सबसे अच्छा विकल्प है क्योंकि आने वाले समय में इसकी मांग तेजी से बढ़ने वाली है और अगर आप यह व्यवसाय करते हैं तो आपको सरकार की तरफ से भी पूरा सहयोग प्रदान किया जाता है।

**जैव ईंधन उत्पादन:** जैव ईंधन भविष्य का उत्पाद है इसलिए यह बेस्ट प्यूचर बिजनेस आइडियाज में से एक है। जैव ईंधन का उत्पादन रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके बायोमास का उपयोग करके किया जाता है। जैव ईंधन टिकाऊ ईंधन है। जैव ईंधन का उपयोग वाहन में बायो-डीजल के साथ-साथ औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी किया जा सकता है। जैव ईंधन उत्पादन एक आशाजनक बिजनेस विकल्प है। यदि आपके पास विशेषज्ञता है तो आप जैव ईंधन उत्पादन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अपने प्यूचर बिजनेस आइडियाज के बारे में प्लान करके इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं।

भविष्य के व्यावसायिक विचारों की सूची अंतर्हीन है और यह और भी लंबी हो सकती है। हालांकि, हमने आने वाले वर्षों के लिए सबसे अच्छे भविष्य के व्यावसायिक विचारों को शामिल किया है।

## असम में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी डसॉल्ट, 240 करोड़ रुपये का करेगी निवेश : हिमंत बिस्वा सरमा

परिवहन विशेष न्यूज

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि पेरिस स्थित डसॉल्ट समूह की प्रौद्योगिकी शाखा डसॉल्ट सिस्टम्स असम में एयरोस्पेस और रक्षा ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिक वाहन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी। इस परियोजना पर 240 करोड़ का निवेश किया जाएगा।

सरमा ने गुवाहाटी में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा, असम कैबिनेट की बैठक ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है जिसके तहत डसॉल्ट की एक कंपनी जो राफेल विमान, 3डी प्रिंटिंग और नई पीढ़ी की तकनीक पर काम करती है, असम में एयरोस्पेस और रक्षा ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिक वाहन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से असम के युवाओं को विमानन उद्योग, रक्षा, एयरोस्पेस, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिक वाहन इंजीनियरिंग में काम करने के लिए आकर्षित किया जाएगा। यह परियोजना 240 करोड़ रुपये की होगी, जिसमें कंपनी करीब 200 करोड़ रुपये का निवेश करेगी और राज्य सरकार 40 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

सरमा ने शुक्रवार को गुवाहाटी में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा, "असम कैबिनेट की बैठक ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है जिसके तहत



डसॉल्ट की एक कंपनी जो राफेल विमान, 3डी प्रिंटिंग और नई पीढ़ी की तकनीक पर काम करती है, असम में एयरोस्पेस और रक्षा ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिक वाहन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से असम के युवाओं को विमानन उद्योग, रक्षा, एयरोस्पेस, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिक वाहन इंजीनियरिंग में काम करने के लिए

आकर्षित किया जाएगा। यह परियोजना 240 करोड़ रुपये की होगी, जिसमें कंपनी करीब 200 करोड़ रुपये का निवेश करेगी और राज्य सरकार 40 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

उन्होंने कहा कि इससे पहले राज्य सरकार ने टाटा के साथ मिलकर इसी तरह की परियोजनाएं की हैं और राज्य के पॉलिटेक्निक में भी यह परियोजना चल

रही है। उन्होंने कहा, "गुवाहाटी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह हब होगा। यहां से असम के करीब 50 कॉलेजों को स्पोक मॉडल के जरिए प्रशिक्षित किया जाएगा।"

उन्होंने कहा, "कंपनी एआई, रोबोटिक्स, रक्षा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करती है और दुनिया में एक अग्रणी प्रौद्योगिकी संगठन है।"

## महिंद्रा एक्सयूवी 3XO का वेटिंग पीरियड बढ़ा, डिमांड इतनी कि करना पड़ रहा आधे साल तक इंतजार

महिंद्रा एक्सयूवी 3XO की डिमांड इसके दोबारा लॉन्च होने के बाद से बढ़ी है। इसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों को इसकी डिलिवरी के लिए आधा साल तक का इंतजार करना पड़ रहा है। इसके बेस वैरिएंट की वेटिंग पीरियड 6 महीने तक का है। XUV 3XO की कीमत 7.49 लाख रुपये से लेकर 15.49 लाख रुपये के बीच है।

**नई दिल्ली।** अप्रैल में XUV 300 के फेसलिफ्ट XUV 3XO को लॉन्च होने के बाद से इसकी डिमांड पहले से ज्यादा बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी हर महीने 9,000-10,000 यूनिट प्रति महीने बिक्री हो रही है, जो अपडेटेड मिलने से पहले करीब 4,000 यूनिट थी। इसकी बुकिंग को लेकर अब हाल यह है कि लोगों को इस गाड़ी की डिलिवरी के लिए आधे साल तक का इंतजार करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं कि Mahindra XUV 3XO के किस वैरिएंट के लिए कितना इंतजार करना पड़ रहा है।



**Mahindra XUV 3XO:** कितना वेटिंग पीरियड  
महिंद्रा XUV 3XO के बेस MX1 पेट्रोल वैरिएंट का वेटिंग पीरियड सबसे ज्यादा 6 महीने तक का है। वहीं, इसके उच्च-स्पेक AX5L, AX7 और AX7L पेट्रोल वैरिएंट पर करीब दो से तीन महीने का वेटिंग पीरियड है। इसके मिड-स्पेक AX5 ट्रिम का वेटिंग पीरियड चार महीने तक है।

महिंद्रा XUV 3XO के सभी वैरिएंट का वेटिंग पीरियड एक महीने तक के लिए है।

**Mahindra XUV 3XO: इंजन ऑप्शन**  
महिंद्रा XUV 3XO में कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। इसमें डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, लेवल 2 ADAS तकनीक और पैनोरमिक सनरूप भी दिया गया है। यह तीन इंजन ऑप्शन के साथ आती है, जो 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल, 1.2-लीटर डायरेक्ट इंजेक्शन पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल है। इसके पेट्रोल वाले इंजन को 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। वहीं डीजल इंजन को मैनुअल और 6-स्पीड AMT ऑप्शन मिलता है।

**Mahindra XUV 3XO: कीमत**  
महिंद्रा XUV 3XO की एक्स-शोरूम कीमत 7.49 लाख रुपये से 15.49 लाख रुपये तक है। यह नू ट्रिम में आती है।

# कृषि निर्यात बढ़ाने का मार्ग



विजय गर्ग

**समस्या की जड़ तक कोई भी राजनीतिक दल और सरकारें नहीं जाना चाहती। ऐसा नहीं है कि समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो सकता, किन्तु वहां तक पहुंचने और व्यावहारिक समाधान ढूंढने में पापड़ बेलने पड़ते हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने महिला चिकित्सक से बलात्कार के बाद हत्या के मामले में वही किया है जो अब तक ऐसे मामलों में दूसरे राज्य या केंद्र सरकार करती रही हैं।**

खेत से खाने की मेज तक सप्लाई श्रृंखला को गतिदेकर, वैश्विक व भारतीय खाद्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा दे कर तथा खेतों पर ही खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा दे कर किसानों को बेहतर मुनाफा सुनिश्चित करने के साथ ही फसल कटने के बाद होने वाले नुकसानों से बचा जा सकता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इस दिशा में नेतृत्वकारी भूमिका अदा करते हुए नई दिल्ली में 19-22 सितंबर तक 'वर्ल्ड फूड इंडिया' का आयोजन कर रहा है। इसके साथ ही 2024-25 के केन्द्रीय बजट में कृषि क्षेत्र विकास के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इस फंडिंग के माध्यम से जलवायु समस्याओं से निपटने तथा उत्पादकता, खोज एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

यह कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए जरूरी है जिसमें 8 प्रतिशत गिरावट आई है। यह 2022-23 में 53.52 बिलियन डालर से घट कर 2023-24 में 48.9 बिलियन डालर रह गया। 2014-23 के बीच कृषि निर्यात औसतन केवल 2 प्रतिशत वार्षिक की गति से बढ़े। उल्लेखनीय है कि पांच उत्पाद चावल, गेहूँ, मांस, मसाले, चीनी तथा चाय काफी का हिस्सा कुल कृषि उत्पाद निर्यात में 50 प्रतिशत से अधिक है। कभी-कभी घरेलू मांग पूरी करने तथा मुद्रास्फूर्ति पर नियंत्रण के लिए निर्यात पर नियंत्रण लगाना पड़ता है। हमारे कृषि निर्यातों का केवल प्रतिशत प्रसंस्कृत या मूल्य-संवर्धित है। पिछले दशक में इस आंकड़े में लगभग कोई परिवर्तन नहीं आया है। हालांकि, ज्यादा टेक-आधारित आपरेशनल आकार और उत्पादन क्षमता तथा विश्व बाजार में अंतरराष्ट्रीय मानक पूरा करने को देखते हुए यह काफी है। लेकिन 111 बिलियन प्रसंस्कृत खाद्य एवं पेय पदार्थों के निर्यातक स्वटजरलैंड की 'नेस्ले' जैसी कंपनियों की सफलता को देखते हुए स्पष्ट होता है कि तकनीक और शोध के प्रयोग से क्या संभव हो सकता है। 19 बिलियन डालर टनटोवर वाली उल्लेखनीय भारतीय घरेलू प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद बेचने वाली 'अमूल' आपरेशनल क्षमता, उत्पादन क्षमता तथा अंतरराष्ट्रीय मानक पूरा करने के मामले में नेस्ले से बहुत पीछे है। इसके बावजूद समुचित समर्थन और दृष्टिकोण के चलते वह भी ऐसी ही सफलता प्राप्त कर सकती है। प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों का निर्यात लगभग 1 ट्रिलियन डालर वार्षिक है जिसमें 63 बिलियन डालर के साथ जर्मनी सविस्त्र स्थानों पर है। इसके बाद 58 बिलियन डालर के साथ अमेरिका, 57 बिलियन डालर के साथ



नीदरलैंड, 53 बिलियन डालर के साथ चीन तथा 50 बिलियन डालर के साथ फ्रांस का स्थान है। दक्षिणपूर्व एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के बड़े निर्यातक हैं।

हालांकि, मूल्य संवर्धित कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने वाली कृषि-निर्यात नीति लागू होने के बाद पिछले पांच साल में भारत के मूल्य-संवर्धित निर्यात में 6.5 बिलियन डालर की वृद्धि हुई है और यह कुल 15 बिलियन डालर तक पहुंच गया है। लेकिन इसके बावजूद इससे वैश्विक रैंक में मामूली सुधार ही हुआ है और हम 21वें स्थान से ऊपर उठ कर 17वें स्थान पर पहुंच सके हैं। इस स्थिति में निश्चित रूप से सुधार हो सकता है। 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत दुनिया में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 300 मिलियन टन उत्पादन के साथ यह चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। लेकिन भारत में प्रसंस्करण स्तर बहुत कम है। यह फलों के लिए 4.5 प्रतिशत, सब्जियों के लिए 2.7 प्रतिशत, दूध लिए 21.1 प्रतिशत, मांस के लिए 34.2 प्रतिशत और मछलियों के लिए 15.4 प्रतिशत है। इसकी तुलना में चीन में प्रसंस्करण 25-30 प्रतिशत तथा पश्चिमी देशों में 60-80 प्रतिशत है।

प्रसंस्करण क्षमता में इस कमी के कारण भारत में उत्पाद का काफी हिस्सा बेकार चला जाता है। अनुमान है कि देश में फसल कटाई के बाद बरबादी का स्तर पूरी सप्लाई श्रृंखला में 18 से 25 प्रतिशत के बीच है, हालांकि फलों और सब्जियों के मामले में यह लगभग 45 प्रतिशत है। नीति आयोग का अनुमान है कि फसल कटाई के बाद बरबादी का स्तर 10 करोड़ रुपये की बरबादी होती है। इस स्थिति में सुधार के लिए खेतों पर ही समुचित छंछाई और प्रोडिंग तथा प्रसंस्करण बढ़ाने की आवश्यकता अनुभव की जाती है। कृषि प्रोत्साहनों में परिवर्तन कर किसानों को इस बात के लिए प्रेरित करना जरूरी है कि वे खेतों तथा उसके निकट बरबादी रोकने के प्रयास करें।

2020 में केन्द्र सरकार ने एक ट्रिलियन रुपये के कृषि ढांचगत फंड की घोषणा की थी ताकि कोल्ड चेन श्रृंखला - तथा फसल कटाई के बाद प्रबंधन ढांचा खेतों तथा फसल संग्रह केन्द्रों पर बनाने के लिए मध्यम से दीर्घकालीन अवधि की कर्ज फाइनेंसिंग की जा सके। तमिलनाडु द्वारा हाल ही में घोषित नई खाद्य प्रसंस्करण नीति में एक कदम आगे बढ़ कर बरबादी रोकने तथा कृषि उत्पाद का मूल्य बढ़ाने के कदम उठाए गए हैं। इस नीति में कृषि उत्पादक संगठनों एफपीओ तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा के लिए वित्तीय सहायता तथा केन्द्रीय योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं।

लेकिन यह उल्लेखनीय है कि पंजाब ने अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है, जबकि पड़ोसी राज्य हरियाणा में प्रतिबद्ध एग्रीबिजनेस खाद्य प्रसंस्करण नीति बनाई गई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रोडक्शन लिंकड इंसेटिव स्कीम- पीएलआईएसएफआई के लिए 2021-22 से 2026-27 के बीच 10,900 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इसका उद्देश्य वैश्विक रूप से प्रतियोगी फर्मों को भारत में उत्पाद व कृषि निर्यात में आकर्षित करना है। इस योजना का लक्ष्य प्रसंस्करण क्षमता में सुधार, भारतीय ब्रांडों को मजबूत करना, विश्व बाजार में उपस्थिति बढ़ाना, रोजगार सृजन तथा किसानों की आमदनी बढ़ाना है। मई, 2024 तक पीएलएसएफआई के 90 प्रतिशत धन का प्रयोग नहीं हुआ था। सरकार ने 158 एसएमई लाभार्थियों को केवल 1,073 करोड़ रुपये दिए थे और इस प्रकार योजना का अराध रूप यैवत जाने के बावजूद उसका केवल 10 प्रतिशत धन प्रयोग हुआ था। इस प्रकार पैसे के बहुत कम प्रयोग से ज्यादा केन्द्रित नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता उजागर होती है।

पीएलआई योजना का लक्ष्य वैश्विक प्रतियोगिता क्षमता तथा निर्यात बढ़ाना है। इसे

देखते हुए एसएमई को वैश्विक स्तर पर स्थापित एंकर' फर्मों के साथ संयुक्त उद्यम बनाने चाहिए। पिछले दशक में भारत ने शत प्रतिशत एफडीआई अनुमति के बाद 500 बिलियन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्राप्त किया। इसे देखते हुए खाद्य प्रसंस्करण को भारत का 'सनराइज उद्योग' समझा जाना चाहिए जो किसानों को प्रभावी रूप से लाभ दिलाए, एमएसपी के प्रति बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने तथा मूल्य संवर्धन और उद्योग में समन्वय स्थापित करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कृषि के विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण को रणनीतिक महत्व देना जरूरी है। दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश देश के नाते हम धरती पर पर्यावरण दबाव का अनुभव कर रहे हैं। इसके कारण मृदा क्षरण, जैवविविधता में कमी तथा जल संकट जैसे परिस्थितिकी मुद्दे सामने आ रहे हैं। व्यापक खाद्य व्यवस्थाओं में बरबादी रोकना जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों से बचने के लिए बहुत जरूरी है। इससे खेतों से लेकर खाने की मेज तक खाद्य सप्लाई बेहतर करने में सहायता मिलेगी तथा हानिकारक उत्सर्जन घटेगा। खाद्य प्रसंस्करण की अद्यतन तकनीकों के प्रयोग, वैश्विक स्तर पर स्वीकृत गुणवत्ता मानकों को मंजू करके तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच खोलने के माध्यम से यह केन्द्रित रणनीति बड़ी वैश्विक फर्मों को आकर्षित कर हमारे लक्ष्य पूरे कर सकती है। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में 'एपल' लक्षित दृष्टिकोण की सफलता का एक माडल है। यही माडल विभिन्न उद्योगों के इसलिए लागू किया जाना चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को समर्थन देना चाहिए। इसके अलावा एमएसएमई फर्मों के साथ कृषि उत्पादक संगठनों एफपीओ तथा एसएमई के बीच साझेदारियों को बढ़ावा देना चाहिए।

**सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार गली कौर चंद वाली मंडी हरजी राम वाली मलोट पंजाब - 152 107**

## संपादक की कलम से

### हिंदी पर बाजार का कब्जा

'भाषा ही किसी जाति की सभ्यता को सबसे अलग झलकाती है, यही उसके हृदय के भीतरी कल-पुजे का पता देती है। किसी जाति को अशक्त करने का सबसे सहज उपाय उसकी भाषा को नष्ट करना है।' 1912 में प्रख्यात आलोचक व निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह बात कही थी। उदारवाद का बिगुल फूटते बहुतेरे टीवी चैनल आ गए। अखबार रंगीन और चिकने पन्ने वाले हुए और ग्लोबलिस्टों की नई-नई टुकड़ियां उनके संपादकीय पन्नों पर कब्जा करने लगीं। खुले दरवाजे पर तोरण की मानिंद लटकते पिंजरे में बैठे तोतों की तरह वे सुबह से शाम तक यह बताने लगे कि इस देश को 21वीं सदी में ले जाने के लिए हिंदी असमर्थ है। यह कठिन और दुरुह है। हिंदी को बिना शोध के टेक्नोक्रैटली से दूर किया गया। नतीजतन, धड़ाधड़ हिंदी के स्थापित और प्रचलित शब्दों को, जो संप्रेष्य थे, अपदस्थ कर उनकी जगह अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग समाचारपत्रों में होने लगा। देशहित में हिंदी के विस्थापन को नए चिंतकों ने अनिवार्य मान लिया। अंग्रेजी के तीसरे दर्जे के कथित विद्वानों-लेखकों को हिंदी मीडिया के नाते हम धरती पर पर्यावरण दबाव का अनुभव कर रहे हैं। इसके कारण मृदा क्षरण, जैवविविधता में कमी तथा जल संकट जैसे परिस्थितिकी मुद्दे सामने आ रहे हैं। व्यापक खाद्य व्यवस्थाओं में बरबादी रोकना जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों से बचने के लिए बहुत जरूरी है। इससे खेतों से लेकर खाने की मेज तक खाद्य सप्लाई बेहतर करने में सहायता मिलेगी तथा हानिकारक उत्सर्जन घटेगा। खाद्य प्रसंस्करण की अद्यतन तकनीकों के प्रयोग, वैश्विक स्तर पर स्वीकृत गुणवत्ता मानकों को मंजू करके तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच खोलने के माध्यम से यह केन्द्रित रणनीति बड़ी वैश्विक फर्मों को आकर्षित कर हमारे लक्ष्य पूरे कर सकती है। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में 'एपल' लक्षित दृष्टिकोण की सफलता का एक माडल है। यही माडल विभिन्न उद्योगों के इसलिए लागू किया जाना चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को समर्थन देना चाहिए। इसके अलावा एमएसएमई फर्मों के साथ कृषि उत्पादक संगठनों एफपीओ तथा एसएमई के बीच साझेदारियों को बढ़ावा देना चाहिए।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार गली कौर चंद वाली मंडी हरजी राम वाली मलोट पंजाब - 152 107

का आधुनिकीकरण एक-दूसरे के पर्याप्त समझ लिए गए। विदित है कि हिंदी पहले बुद्धिवाद और समावेशी राष्ट्रवाद की वाहक मानी जाती थी, जो आज भी है, किन्तु बाजार ने इसे कहीं का नहीं रहने दिया। इसके सटीक उदाहरण आध्यात्मिक बाजार, मल्टी प्लेक्स और क्रिकेट के मैदान में दिख रहे हैं। क्या अंग्रेजी अपनाने से ही जान या सोच की प्रक्रिया आधुनिक हो जाएगी? उल्लेखनीय है कि एक उत्तर-औपनिवेशिक मामला भाषा, साहित्य और संस्कृति में अस्मिता की राजनीति का है। विडंबना है कि हम टेक्नोलॉजी और आधुनिकीकरण के जितने शिखर पर चढ़ते जा रहे हैं, सामाजिक विविधता उतनी ही तेजी से सामाजिक भिन्नता में बदलती जा रही है। इसी कारण प्रांतीय संस्कृतिक हाहाकार मच रहा है। प्रतीति के दृश्य दिख रहे हैं। आज समाज को जो पीढ़ियां नेतृत्व दे रही हैं, उनकी नैतिक गड़बड़ियों के मूल में कहीं भाषा के प्रति उनकी असावधानी और गैर जिम्मेदाराना सलूक तो नहीं है। कभी हिंदी का जन्म बाजार में हुआ था, बाजार में ही उसका विकास हुआ, पर आज बाजार ही उसे तहस-नहस कर रहा है। इसलिए, इसका विकास व भविष्य बाजार के हाथ में है। शिक्षा के बाजारीकरण ने रही-सही कसर भी पूरी कर दी। अंग्रेजी ने तो आधुनिकता का अर्थ संकुचित कर दिया है, जबकि तबे काल खंड से हिंदी आधुनिकता को व्यापकता प्रदान करते आया है। दुःखद पहलू है कि विश्व-बोध के लिए ग्लोबल होना आवश्यक है, जिसमें बाधक राष्ट्र है। एक अफसर ने तो यह कह कर चौंका दिया कि भारतीय भाषाएं अवधारणात्मक चिंतन के लिए अंग्रेजी की तुलना में उतनी योग्य नहीं हैं। हिंदी केवल भाषा ही नहीं, यह भारत की स्वत्व, अस्मिता और संस्कृति की भी प्रतीक है। समाज में चेतना जागरण, देशभक्ति का भाव, अपना संस्कृति और जीवन मूल्यों का ज्ञान भाषा के माध्यम से ही किया जा सकता है। आज भी हिंदी ही हम सबको एकता के सूत्र में बांध सकती है और समाज तथा राष्ट्र को समृद्धशाली बना सकती है। अणु कालांतर में महाशक्ति का दर्जा पाने वाले देशों की अदालतों में मातृभाषा को अपनाया जाता है।

## कविता

### जिद बड़ी या जिंदगी!

कोलकाता में डॉक्टर अब भी काम पर नहीं लौटे हैं। बंगाल सरकार ने संवाद और समझौते का जो प्रयास किया था, वह आंदोलनकारी डॉक्टरों की जिद ने नाकाम कर दिया। एक नाटकीय घटनाक्रम जरूर सामने आया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, हाथ जोड़ कर, बंगाल की जनता से माफ़ी मांगी है। यदि जनता चाहेगी, तो वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तक देने को तैयार है। उन्होंने कहा है कि वह 'कुर्सी की भूखी' नहीं है, बल्कि न्याय की पक्षधर है। हालांकि रैप-मर्डर की शिकायत डॉक्टर बिट्टिया के माता-पिता और आंदोलनकारी डॉक्टरों ने कभी भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग नहीं की। इसे विपक्षियों ने मुद्दा बनाकर राजनीति करने की कोशिश की है। डॉक्टरों ने मुद्दा बनाकर राजनीति करने की कोशिश की है। डॉक्टरों की लड़ाई लड़ रही है, ताकि डॉक्टर बिट्टिया की आत्मा को सुख, शांति मिल सके। डॉक्टर मुख्यमंत्री से संवाद करने सचिवालय गए थे। उनकी संख्या 32 बताई गई है, जबकि सरकार ने 15 डॉक्टरों को ही, प्रतिनिधि के तौर पर, आमंत्रित किया था। बहरहाल बंगाल सरकार ने उस संख्या को भी अनुमति दे दी। राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत और पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार डॉक्टरों को समझाते रहे कि विरोध-प्रदर्शन का यह सिलसिला टूटना क्यों जरूरी है। बादगीतों का सीधा प्रसारण संभव नहीं है। अलबत्ता संवाद की रिपोर्टिंग जरूर कराई जाएगी, लेकिन आक्रोशित डॉक्टर लगातार यह सवाल करते रहे कि सीधे प्रसारण से सरकार डटती क्यों है? डॉक्टर 'नबन्नी' सचिवालय में गिरफ्तार तक तो पहुंच गए, लेकिन उस कक्ष के भीतर नहीं गए, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2.10 घंटे से आंदोलनकारी डॉक्टरों की प्रतीक्षा कर रही थीं। नतीजतन संवाद का जो सेंटर बनाया गया था, वह ढह गया। डॉक्टर लौट गए और धरना-स्थल पर जाकर बैठ गए। मुख्यमंत्री ने इस्तीफे तक की पेशकश की और बंगाल की जनता से माफ़ी मांगी कि वह डॉक्टरों को ड्यूटी पर वापस लाने में नाकाम रही। यह ममता बनर्जी की 'भावुक राजनीति' भी हो सकती है, ताकि अधिकतर लोग उनसे नाराज न हों और समर्थन समाप्त करने पर आमादा न हो जाए! बंगाल के अलग-अलग हिस्सों में विपक्षी दल आक्रामक होकर विरोध-प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। डॉक्टर तो आंदोलित हैं ही, लेकिन उनके समर्थन में विभिन्न सामाजिक आंदोलन भी छिड़ गए हैं, लिहाजा राज्य में अराजकता की स्थिति है। सडकों पर भीड़ है, तो पुलिसकर्मियों भी है। अदालतों में अलग केंस चल रहे हैं। ममता की यह राजनीति आजमाई हुई है। बहरहाल डॉक्टरों का आंदोलन अब एक जिद का रूप धारण कर चुका है। सर्वोच्च अदालत ने उन्हें काम पर लौटने का समय दिया था, वह गुजर चुका है। शीघ्र अदालत डॉक्टरों के सरोकारों की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन आंदोलनकारियों को भरोसा ही नहीं है। यह जिद ही नहीं, अवमानना भी है। डॉक्टर जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने लगे हैं, क्योंकि आरजी कर अस्पताल में इलाज न मिलने से अभी तक 27 लोगों की अकाल मौत हो चुकी है और 7 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। यकीनन डॉक्टर बिट्टिया के प्रसंग पर पूरा देश गुस्से में रहा है, क्षुब्ध रहा है, असंख्य विरोध-प्रदर्शन भी किए गए हैं। डॉक्टरों के साथ सहायुक्ति है, संवेदना है, क्योंकि बिट्टिया चिकित्सकों की सुरक्षा वाकई चिंतित सरोकार है, लेकिन काम छोड़ कर आंदोलन ही जारी रखना या जुलूस निकालना अथवा डॉक्टर होकर धरने पर खाली बैठे रहना, दरअसल अपनी पेशेवर प्रतिबद्धता से मुंह मोडना है।

## विजय गर्ग

# ओजोन थैरेपी आपकी समग्र उपचार यात्रा को सशक्त बनाती है

ओजोन थैरेपी, एक समग्र उपचार दृष्टिकोण जो दुनिया भर में गति प्राप्त कर रहा है, ओजोन की शक्ति का उपयोग करता है - भलाई को बढ़ावा देने के लिए एक प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली गैस। आयुर्वेद के साथ संयुक्त होने पर, ओजोन थैरेपी स्वास्थ्य और उपचार के लिए एक सहक्रियात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है। आयुर्वेदिक सिद्धांत ओजोन थैरेपी के एकीकरण का मार्गदर्शन करते हैं, व्यक्तिगत संविधान और असंतुलन के लिए व्यक्तिगत उपचार योजनाओं पर जोर देते हैं। प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर, यह समग्र दृष्टिकोण समग्र कल्याण, जीवन शक्ति और दीर्घायु को बढ़ावा देते हुए बीमारी के मूल कारणों को संबोधित करता है। ओजोन थैरेपी के पीछे का तंत्र: इसकी चिकित्सीय कार्यवाही को समझना ओजोन थैरेपी शरीर की जैविक प्रक्रियाओं के साथ एक आकर्षक परस्पर क्रिया के माध्यम से संचालित होती है, जो सेलुलर स्तर पर अपना प्रभाव डालती है। इसकी क्रियाविधि को समझने से इसके चिकित्सीय लाभों पर प्रकाश पड़ता है। प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियाँ (आरओएस) यह शरीर के भीतर प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों (आरओएस) के उत्पादन को प्रेरित करता है। ये आरओएस सिग्नलिंग अणुओं के रूप में कार्य करते हैं, जो जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं का एक झरना शुरू करते हैं जो विभिन्न सेलुलर प्रतिक्रियाओं को सक्रिय करते हैं। सेलुलर चयापचय यह ऑक्सीजन के उपयोग और ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाकर सेलुलर चयापचय को प्रभावित करता है। उतकों तक ऑक्सीजन वितरण बढ़ाकर, ओजोन

थैरेपी सेलुलर श्वसन को अनुकूलित करती है, जिससे एटीपी संश्लेषण और चयापचय दक्षता में सुधार होता है। प्रतिरक्षा मॉड्यूलेशन यह प्रतिरक्षा समारोह पर गहरा प्रभाव डालता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को विनियमित करने के लिए एक इन्फ्लेमेटोरी मॉड्यूलेशन के रूप में कार्य करता है। यह मैक्रोफेज, टी लिम्फोसाइट्स और प्राकृतिक हत्याका शोशिकाओं जैसे प्रतिरक्षा कोशिकाओं की गतिविधि को बढ़ाता है, जिससे रोगजनकों, विषाक्त पदार्थों और असामान्य कोशिकाओं को पहचान और उन्मूलन की सुविधा मिलती है। समग्र उपचार का उपयोग: ओजोन थैरेपी के आयुर्वेदिक लाभ ओजोन थैरेपी, समग्र स्वास्थ्य प्रथाओं में मान्यता प्राप्त करने वाली एक पद्धति, आयुर्वेदिक सिद्धांतों के अनुरूप लाभ का एक स्पेक्ट्रम प्रदान करती है। आयुर्वेद में, स्वास्थ्य को मन, शरीर और आत्मा के सामंजस्यपूर्ण संतुलन के रूप में देखा जाता है और उपचार का उद्देश्य इस संतुलन को बहाल करना है। विषहरण सहायता: परिसंचरण और चयापचय प्रक्रियाओं को बढ़ाकर शरीर से विषाक्त पदार्थों को खत्म करने में सहायता करता है। यह शरीर के जन्मजात विषहरण मार्गों का समर्थन करता है, समग्र कल्याण और जीवन शक्ति को बढ़ावा देता है। सूजन रोधी गुण: सूजन के मार्गों को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता के साथ, यह पुरानी सूजन को कम करता है, जो अक्सर विभिन्न बीमारियों की जड़ होती है। ऊतक उपचार और बहाली को बढ़ावा देकर, यह सूजन की स्थिति से जुड़े लक्षणों को कम करता है, समग्र उपचार को बढ़ावा देता है। प्रतिरक्षा प्रणाली में वृद्धि: साइटोटॉक्स और प्रतिरक्षा कोशिकाओं के उत्पादन को उत्तेजित

करता है, शरीर की रक्षा तंत्र को मजबूत करता है। यह प्रतिरक्षा वृद्धि रोग की रोकथाम के आयुर्वेदिक सिद्धांतों के अनुरूप है, जो रोगजनकों और संक्रमणों के खिलाफ लचीलापन सुनिश्चित करती है। बुढ़ापा रोधी लाभ: कोलेजन उत्पादन को उत्तेजित करता है, त्वचा की लोच में सुधार करता है और उम्र बढ़ने के संकेतों को कम करता है। नियमित उपयोग से, यह महीने रेखाओं, झुर्रियों और उम्र के धब्बों को कम करने में मदद करता है, जिससे रंगत युवा बनी रहती है। ओजोन थैरेपी, बुढ़ापा रोधी उपचार, मुँहासे उपचार मूड में सुधार: एंडोर्फिन और न्यूरोट्रान्समीटर जारी करता है, खुशी और कल्याण को भावनाओं को बढ़ावा देता है। यह तनाव, चिंता और अवसाद को कम करता है, भावनात्मक संतुलन और मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देता है। मुँहासे उपचार: प्रभावी क्षेत्रों पर स्थानीय रूप से ओजोन लगाने से मुँहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया और सूजन को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, ओजोनेटेड तेल और क्रीम मुँहासे उपचार त्वचा को शांत और ठीक करते हैं, साफ रंग को बढ़ावा देते हैं और समग्र त्वचा देखभाल का समर्थन करते हैं। कुल मिलाकर अच्छी तरह जा रहे: अपने बहुमुखी उपचार दृष्टिकोण के साथ, ओजोन थैरेपी को शांत और ठीक करते हैं, साफ रंग के साथ सहजता से एकीकृत होती है, जिससे समग्र कल्याण और जीवन शक्ति में वृद्धि होती है। यह समग्र उपचार के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हुए, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप वैयक्तिकृत उपचार योजनाएँ प्रदान करता है। ओजोन थैरेपी को समग्र उपचार पद्धतियों में एकीकृत करना ओजोन थैरेपी

विभिन्न समग्र उपचार पद्धतियों के साथ सहजता से एकीकृत होती है, उनकी प्रभावकारिता को बढ़ाती है और समग्र कल्याण को बढ़ावा देती है। यहाँ उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे ओजोन थैरेपी को समग्र उपचार पद्धतियों में शामिल किया गया है: ऊर्जा उपचार: सेलुलर जीवन शक्ति को बढ़ावा देने और शरीर के ऊर्जावान मार्गों को संतुलित करके ऊर्जा उपचार प्रथाओं का समर्थन करता है। जब रेकी या एक्स्पेरिमेंट जैसी तकनीकों के साथ जोड़ा जाता है, तो ओजोन थैरेपी भौतिक और सूक्ष्म दोनों स्तरों पर समग्र उपचार की सुविधा प्रदान करता है। दिमागीपन अस्थिर: इस थैरेपी को माइंडफुलनेस प्रथाओं में शामिल करने से शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देकर उनके चिकित्सीय लाभों में वृद्धि होती है। ओजोन थैरेपी के कायाकल्प प्रभाव ध्यान और सांस लेने जैसी तकनीकों के साथ जोड़ा जाता है, जो विश्राम, तनाव में कमी और भावनात्मक संतुलन को बढ़ाते हैं। पोषण चिकित्सा: पोषक तत्वों के अभाव और सेलुलर चयापचय को अनुकूलित करके पोषण चिकित्सा के साथ आहार और पूरकता के साथ जोड़ा जाता है, तो ओजोन थैरेपी शरीर को पोषण संबंधी जरूरतों का समर्थन करती है, समग्र उपचार दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से पूरक करती है। ओजोन थैरेपी के माध्यम से टीकाकरण के बाद के लक्षणों के लिए समग्र समर्थन COVID-19 टीकाकरण के बाद, कुछ व्यक्तियों को थकान, खराश, बुखार और रक्त के थक्के जैसे हल्के से मध्यम दुष्प्रभाव का अनुभव हो सकता है। ओजोन थैरेपी अपने

एंटी-इंफ्लेमेटरी और इम्यून-मॉड्यूलेटिंग प्रभावों के माध्यम से इन लक्षणों को संबोधित करके समग्र सहायता प्रदान करती है। सूजन को कम करके और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाकर, ओजोन थैरेपी असुविधा को कम करने और टीकाकरण के बाद तेजी से रिकवरी को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। यह एकीकृत दृष्टिकोण शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रियाओं का समर्थन करता है, व्यक्तियों को टीके से संबंधित लक्षणों को प्रबंधित करने और समग्र कल्याण को बढ़ाने के लिए एक सौम्य और प्रभावी साधन प्रदान करता है। ओजोन थैरेपी को समग्र उपचार पद्धतियों में शामिल करने से विषहरण को बढ़ावा देने, सूजन को कम करने और प्रतिरक्षा समारोह को बढ़ाकर समग्र कल्याण में वृद्धि होती है। ऊर्जा उपचार, माइंडफुलनेस प्रथाओं और पोषण चिकित्सा जैसे तौर-तरीकों के साथ सहजता से एकीकृत होकर, यह व्यापक देखभाल प्रदान करता है जो मन, शरीर और आत्मा के अंतर्संबंधों को संबोधित करता है, इष्टतम स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बढ़ावा देता है। ओजोन थैरेपी को समग्र स्वास्थ्य देखभाल में एकीकृत करना स्वाभाविक रूप से श्वसन स्वास्थ्य को अनुकूलित करने में एक महत्वपूर्ण प्रगति है, जब इसे पूरक तौर-तरीकों के साथ जोड़ा जाता है, तो यह बेहतर श्वसन स्वास्थ्य और समग्र जीवन शक्ति की दिशा में एक परिवर्तनकारी यात्रा का मार्ग प्रशस्त करता है। आइए ओजोन थैरेपी को आशा की किरण के रूप में अपनाएं, जो हमें उन्नत कल्याण और आनंदमय जीवन के साथ प्रचुर भविष्य की ओर मार्गदर्शन करती है।

# स्थानीय संस्कृतियों का क्षरण और डिजिटल उपनिवेशीकरण का उदय

## विजय गर्ग

हम तेजी से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भरोसा कर रहे हैं जिसका स्थानीय संस्कृतियों और विचार प्रक्रियाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। यह हमारी सांस्कृतिक पहचान के भविष्य के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा करता है एक समय था जब एक गाँव के लोग एक दूसरे को जानते थे। किसी व्यक्ति के व्यवहार में एक मिन्ट का बदलाव दूसरों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित कर देगा। उस समाज में बच्चे सुरक्षित थे। हमारे देश के प्रत्येक शहर या प्रत्येक स्थान की अपनी संस्कृति, परंपराएँ, भाषा, खान-पान की आदतें, उत्पादित उत्पाद और यहाँ तक कि बताने के लिए एक कहानी भी अद्वितीय है। उपनिवेशीकरण, बाहरी और आंतरिक दोनों, जो एक समूह द्वारा दूसरे पर नियंत्रण के अभ्यास की विशेषता है, ने इतिहास के पुनर्लेखन पर गहरा प्रभाव डाला है। इसके पीछे कई प्रेरणाएँ रही हैं, जिनमें आर्थिक लाभ, क्षेत्रीय विस्तार, धार्मिक रूपारण और भू-

राजनीतिक शक्ति सहित अन्य विचार शामिल हैं। पहले के समय में, विदेशी लोग ही स्थानीय समुदाय में घुसपैठ करते थे; अब, मूल लोगों के विचार प्रक्रियाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। यह हमारी सांस्कृतिक पहचान के भविष्य के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा करता है एक समय था जब एक गाँव के लोग एक दूसरे को जानते थे। किसी व्यक्ति के व्यवहार में एक मिन्ट का बदलाव दूसरों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित कर देगा। उस समाज में बच्चे सुरक्षित थे। हमारे देश के प्रत्येक शहर या प्रत्येक स्थान की अपनी संस्कृति, परंपराएँ, भाषा, खान-पान की आदतें, उत्पादित उत्पाद और यहाँ तक कि बताने के लिए एक कहानी भी अद्वितीय है। उपनिवेशीकरण, बाहरी और आंतरिक दोनों, जो एक समूह द्वारा दूसरे पर नियंत्रण के अभ्यास की विशेषता है, ने इतिहास के पुनर्लेखन पर गहरा प्रभाव डाला है। इसके पीछे कई प्रेरणाएँ रही हैं, जिनमें आर्थिक लाभ, क्षेत्रीय विस्तार, धार्मिक रूपारण और भू-

कारण लुप्त हो गई हैं। यह उस समय के दौरान रचित साहित्यिक कृतियों में भी परिलक्षित हुआ है। दुर्भाग्य से, उपनिवेशीकरण के साथ, हमने अपने समाज को एकलुप बना दिया। जब हम देश भर में यात्रा करते हैं तो इसे देखा जा सकता है। हमने अपने शहरों में जिस समाज नेती से बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है, उससे हर शहर एक जैसा दिखने लगा है। 90 के दशक के उत्तरार्ध तक, हमारे देश में प्रत्येक स्थान को किसी विशिष्ट भूगोल, किसी विशिष्ट बाजार या यहाँ तक कि किसी व्यक्ति की उपस्थिति से जाना जाता था। फिर भी, इंटरनेट ने एक नए प्रकार का उपनिवेशीकरण ला दिया है जिसने हमारे समाज में घुसपैठ करना शुरू कर दिया है। उपनिवेशीकरण के इस नए रूप को डिजिटल उपनिवेशीकरण के रूप में जाना

जाता है। शब्द डिजिटल उपनिवेशीकरण का तात्पर्य पूरी दुनिया के डिजिटल बुनियादी ढांचे और डेटा पर कई बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी व्यवसायों के प्रभुत्व से है, जिनमें से अधिकांश संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ धनी देशों में स्थित हैं। अपनी सभी दिन-रुतिविक्रम की आवश्यकताओं के लिए, हमने व्यक्तिगत बातचीत की मात्रा को कम करते हुए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अधिक भरोसा करना शुरू कर दिया। इस नई डिजिटल संस्कृति ने हमारे देश के सुदूरतम हिस्सों में भी घुसपैठ कर ली है। फिर भी, इंटरनेट टाइटेन्स हमारे जीवन में हर चीज को प्राथमिकता देते हैं, जिसमें हमें क्या खरीदना चाहिए, हमें किसके साथ दोस्ती करनी चाहिए, कहाँ पढ़ाई करनी है, कौन सा कोर्स करना है और यहाँ तक कि कहाँ बच्चे को जन्म देना है। यह संभावित रूप से स्थानीय परंपराओं और भाषाओं को नष्ट कर सकता है, क्योंकि आज निर्यात किए जाने वाले अधिकांश भाषा

प्राारूप डिजिटल प्लेटफॉर्म के अनुरूप डिजाइन किए गए हैं। लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो भी उपलब्ध है उस पर आंख मूंदकर विश्वास करने लगे। यह तब इतनी गंभीर है कि दिल्ली-एनसीआर के ऑटो और टैक्सि ड्राइवर, जिनके पास उच्च-नेविगेशन कौशल था पहले दिमाग का इष्टतमाल करती हैं। अब गूगल मैप्स पर शिफ्ट हो गए हैं। वैश्विक आईटी दिग्गज विभिन्न कारणों से सार्वभौमिक डिजिटल संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, जिनमें से कई उनके व्यवसाय मॉडल और विकास रणनीतियों से जुड़े हैं। हालांकि यह डिजिटल संस्कृति वैश्विक कनेक्टिविटी, सूचना पहुंच और सहयोग को बढ़ावा देती है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय विविधता और पारंपरिक विचारों और शैली को अस्पष्ट करने की भी क्षमता है। कुछ तकनीकी कंपनियों के हाथों में सत्ता का संकेंद्रण, सांस्कृतिक विलोपन और गोपनीयता ये सभी चिंताएँ इन निगमों के प्रभुत्व से उत्पन्न हुई हैं।

## भारतीय शेयर बाजार के प्रति जारी है विदेशी निवेशकों का आकर्षण, 13 सितंबर तक खरीदे 16,881 करोड़ के शेयर

परिवहन विशेष न्यूज

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) का घरेलू शेयर बाजारों के प्रति आकर्षण बना हुआ है। 9 से 13 सितंबर 2024 के दौरान एफपीआई ने 16881.03 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे हैं। एफपीआई ने सितंबर के पहले सप्ताह में भी इक्विटी बाजारों में 10980 करोड़ रुपये का मजबूत निवेश किया था। यह एफपीआई के बीच घरेलू इक्विटी बाजारों के प्रति बढ़ते भरोसे को भी दर्शाता है।

**नई दिल्ली** | विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) का घरेलू शेयर बाजारों के प्रति आकर्षण बना हुआ है। यही कारण है कि सितंबर के दूसरे सप्ताह में भी एफपीआई घरेलू इक्विटी बाजारों में शुद्ध खरीदार रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के अनुसार, बीते सप्ताह यानी 9 से 13 सितंबर 2024 के दौरान एफपीआई ने 16,881.03 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे हैं। एफपीआई ने सितंबर के पहले सप्ताह में भी इक्विटी बाजारों

में 10,980 करोड़ रुपये का मजबूत निवेश किया था। यह एफपीआई के बीच घरेलू इक्विटी बाजारों के प्रति बढ़ते भरोसे को भी दर्शाता है।

**बढ़ गया एफपीआई निवेश**  
इस निवेश के साथ सितंबर के दौरान भारतीय इक्विटी बाजारों में एफपीआई निवेश बढ़कर 27,861 करोड़ रुपये हो गया है। इससे पहले अगस्त में घरेलू इक्विटी बाजारों में एफपीआई निवेश सिर्फ 7,322 करोड़ रुपये रहा था। कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान इक्विटी बाजारों में एफपीआई का कुल निवेश 70,737 करोड़ रुपये हो गया है।

बाजार के जानकारों का कहना है कि अब विदेशी और घरेलू निवेशकों की निगाह अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की अगली बैठक पर होगी। इस बैठक में ब्याज दरों में कटौती पर फेसला हो सकता है। दूसरी ओर, डेट बाजारों में बीते सप्ताह एफपीआई निवेश में 317 करोड़ रुपये की कमी आई है और सितंबर में डेट बाजारों में कुल एफपीआई निवेश 50 करोड़ रुपये रह गया है। अब डेट बाजारों में इस वर्ष कुल एफपीआई निवेश 1,08,957 करोड़ रुपये हो गया है।



## आपकी सेविंग पर महंगाई पर असर, 10 साल बाद कितनी होगी 1 करोड़ रुपये की वैल्यू

परिवहन विशेष न्यूज

महंगाई लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इसका सीधा असर रुपये की वैल्यू पर पड़ रहा है। 10 साल पहले 1 लाख रुपये की कीमत थी वो आज घट गई है। इसी तरह आने वाले 10 साल के बाद करोड़ रुपये की वैल्यू भी कम हो जाएगी। हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि आने वाले 10-20 साल में करोड़ रुपये की वैल्यू कितनी रह जाएगी।

**नई दिल्ली** | महंगाई की मार कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में भविष्य की चिंता को दूर करने के लिए हम जाँब के साथ निवेश करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आप जिस स्कीम में निवेश कर रहे हैं उसके मैच्योर होने के बाद उस राशि की वैल्यू कितनी रह जाएगी।

दरअसल, हम निवेश अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए करते हैं। अब ऐसे में कई निवेश स्कीम 10-15 साल के बाद मैच्योर होती है। 10-15 साल के बाद रिटर्न राशि तो पता होती है लेकिन उसकी वैल्यू आज की तुलना में कम हो जाती है।

हम आपको बताएंगे कि 10, 20 साल के बाद करोड़ रुपये की वैल्यू कितनी रहने वाली है। लेकिन, इससे पहले जान लेते हैं कि आखिर रुपये

की वैल्यू में समय के साथ गिरावट क्यों आती है।

**क्यों कम होती है पैसों की वैल्यू**

हर साल महंगाई बढ़ रही है। ऐसे में समय के साथ रुपये की वैल्यू कम हो जाती है। इसे ऐसे समझें कि आज सरसों का तेल 150 रुपये लीटर मिल रहा है। वहीं 5 साल पहले इसकी कीमत 70 रुपये थी। ऐसे में आगे के 10 साल बाद तेल की कीमत 300 रुपये लीटर हो सकती है। इस तरह बाकी चीजों जैसे सोने-चाँदी, घर के दाम भी बढ़ रहे हैं। अब उपभोक्ता इन सभी सामानों को तो खरीदेंगे चाहे महंगाई कितनी भी हो और इस तरह रुपये का मूल्य कम होता जाता है। उदाहरण के तौर पर 10 साल पहले 100 रुपये में जहाँ 3-4 सामान खरीदा जा सकता था वहीं, अब 100 रुपये में केवल एक सामान खरीद सकते हैं। ऐसे में महंगाई में तेजी को देखें तो शायद 10 साल के बाद 100 रुपये में कोई सामान न आए। इस तरह 100 रुपये की वैल्यू कम हो सकती है। अगर हम इन्फ्लेशन रेट 6 फीसदी मानते हैं तो 10 साल के बाद 1 करोड़ रुपये की वैल्यू करीब 55.84 लाख रुपये हो जाएगी। इसी तरह 20 साल के बाद 1 रुपये की कीमत लगभग 31 लाख रुपये हो जाएगी।

## जेब पर कम होगा बोझ, कई शहरों में घटी प्याज की कीमतें, आपके शहर में क्या है रेट



पिछले कुछ महीने से Onion Price में तेजी देखने को मिली। बढ़ते प्याज की कीमतों की वजह से महंगाई पर भी इसका असर पड़ा। ऐसे में प्याज की कीमतों में नरमी लाने के लिए सरकार ने 5 सितंबर को फैसला लिया था कि वह सब्सिडी कीमत पर प्याज बेचेगी। इस पहल को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स ने बताया कि कई शहरों में प्याज की कीमत कम हो गई है।

**नई दिल्ली** | देश में प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए सरकार ने सब्सिडी कीमत पर प्याज बेचना शुरू किया था। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स ने आज एक बयान जारी किया। इस बयान के अनुसार देश के कई शहरों में प्याज की कीमत कम हो गई है।

इस महीने 5 सितंबर 2024 को सरकार ने सब्सिडी वाले प्याज बेचने का फैसला किया था। इस फैसले का असर कुछ दिनों में ही दिखना शुरू हो गया। सरकार ने प्याज की कीमतों को कम करने के लिए यह फैसला लिया था। सरकार की इस पहल के बाद राजधानी दिल्ली में प्याज की कीमत 60 रुपये प्रति किलो से घटकर 55 रुपये प्रति किलो हो गई है।

**कई शहरों में कम हुई कीमत**

मंत्रालय ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि राजधानी दिल्ली के अलावा देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी प्याज की कीमत में नरमी आई है। मुंबई में प्याज 61 रुपये प्रति किलो से कम होकर 56 रुपये प्रति किलो हो गया है। चेन्नई में भी प्याज की खूदरा कीमत 65 रुपये से घटकर 58 रुपये प्रति किलो हो गई है।

**सरकार ने शुरू किया पहल**

सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमत पर लगाम कसने के लिए NCCF और NAFED के मोबाइल वैन और आउटलेट के जरिये 35 रुपये प्रति किलो के भाव पर प्याज की बिक्री करना शुरू किया था। सरकार ने यह पहल दिल्ली और मुंबई में शुरू किया था। अब चेन्नई, कोलकाता, पटना, रांची, भुवनेश्वर और गुवाहाटी सहित कई प्रमुख शहरों में यह पहल शुरू की।

अब सरकार सब्सिडी वाले प्याज की सप्लाई बढ़ाने के लिए डिस्ट्रिब्यूशन चैनल को भी शामिल किया है। इसका मतलब है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, केंद्रीय भंडार आउटलेट और मदर डेयरी के सफल स्टोर पर भी सब्सिडी वाले प्याज की बिक्री होगी।

**4.7 लाख टन का बफर स्टॉक**

मंत्रालय ने बताया कि सरकार के पास 4.7 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक है। ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में प्याज की कीमतों में नरमी आ सकती है।

## इन बीमारियों का फ्री में होता है इलाज, सीनियर सिटिजन भी बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड

Ayushman Bharat

Scheme का नाम बदलकर पीएम जनआरोग्य योजनाकर दिया गया है। इस योजना में 5 लाख रुपये का हेल्थ इश्योरेंस मिलता है। पहले इस योजना में 70 साल से ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति शामिल नहीं होते थे पर अब उनको भी कवर किया जाता है। इस आर्टिकल में जानते हैं कि योजना में कौन-सी बीमारियों का फ्री में इलाज होता है।

**नई दिल्ली** | बीमारी कभी उम्र और पैसे देखकर नहीं आती है। लेकिन, जब इलाज की बात आती है तब वित्तीय तौर पर स्थिर रहने की जरूरत है। ऐसे में भारत सरकार ने 2018 में आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Scheme) शुरू किया था। इस योजना का नाम बदलकर पीएम जनआरोग्य योजना (PM Jan Arogya Yojana) कर दिया गया था।

इस योजना में पहले 70 उम्र से ज्यादा वाले सीनियर सिटिजन शामिल नहीं होते थे। लेकिन अब योजना में आयु की सीमा को खत्म कर दिया। इसका मतलब है कि 70 साल से ज्यादा आयु वाले बुजुर्गों का भी इलाज होगा। ऐसे में सवाल आता है कि योजना में किन बीमारियों का इलाज फ्री में होता है।

**किन बीमारियों का होता है फ्री में इलाज**

इस स्कीम में सभी बड़ी-बड़ी बीमारियों का कवर होती है। योजना में 5 लाख रुपये का



इश्योरेंस मिलता है। इसके अलावा देशभर में 29,000 से ज्यादा अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस हेल्थ सर्विसेज की सुविधा भी मिलती है।

आयुष्मान भारत योजना की वेबसाइट के हिस्से से इस योजना में कैसर, हार्ट डिजोज, किडनी से जुड़ी बीमारियाँ, कोरोना, मोतियाबिंद, डेंगू, चिकुनगुनिया, मलेरिया, घुटना और नी रिप्लेसमेंट जैसे गंभीर बीमारियों का इलाज होता है। हालांकि, मोतियाबिंद, सर्जिकल डिलीवरी, और मलेरिया समेत कई बीमारियों का इलाज केवल सरकारी अस्पताल में होती है। इन

बीमारियों को प्राइवेट अस्पताल से हटा दिया गया है।

इसके अलावा प्रोस्टेट कैसर, डबल वॉल्व रिप्लेसमेंट, कोरोनरी आर्टरी बाइपास, पल्मोनरी वॉल्व रिप्लेसमेंट, नी और हिप रिप्लेसमेंट, स्कल बेस सर्जरी, टिश्यू एक्सपेंडर, पीडियाट्रिक सर्जरी, रेंडिएशन ऑर्कोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, एंजियोप्लास्टी विद स्टेंट जैसे गंभीर बीमारी की सर्जरी भी किसी अस्पताल में करवा सकते हैं।

**कहाँ बनगा आयुष्मान कार्ड**

योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थी को आयुष्मान कार्ड (Ayushman Card)

बनवाना होता है। आयुष्मान कार्ड के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अप्लाई किया जा सकता है। ऑनलाइन के लिए <https://pmjay.gov.in/> की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होगा। वहीं, ऑफलाइन के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाकर आवेदन करना होगा।

आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड (Aadhaar Card), पैन कार्ड (PAN Card), ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License), वोटर आईडी (Voter ID) आदि में से किसी को फोटोकॉपी देनी होगी।

## UIDAI ने बढ़ा दी आधार अपडेट की डेडलाइन, अब इस तारीख तक पूरा कर सकते हैं काम

UIDAI ने सभी आधार यूजर्स को फ्री में आधार अपडेट करने का मौका दिया था। वैसे तो आज फ्री आधार अपडेट करने की आखिरी तारीख थी लेकिन अब इस तारीख को बढ़ा दिया गया है। अब आधार यूजर्स 14 दिसंबर 2024 तक फ्री में आधार अपडेट करवा सकते हैं। हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि आप कैसे ऑनलाइन आधार अपडेट करवा सकते हैं।

**नई दिल्ली** | आधार कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। सरकारी या फिर गैर-सरकारी कामों में आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में जरूरी है कि आधार कार्ड में दी गई सभी जानकारी सही हो। इस वजह से आधार कार्ड जारी करने वाली एजेंसी यानी UIDAI ने फ्री आधार कार्ड अपडेट करने की सुविधा दी थी।

UIDAI ने इसके लिए 14 सितंबर 2024 (शनिवार) तय की थी। अब इस

तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। आधार यूजर्स अब 14 दिसंबर तक फ्री में आधार अपडेट करवा सकते हैं। फ्री अपडेट केवल ऑनलाइन ही किया जा सकता है। इसका मतलब है कि ऑफलाइन अपडेट के लिए अपडेशन फीस देनी होगी। हम आपको बताते जा रहे हैं कि आप ऑनलाइन आधार कार्ड कैसे अपडेट कर सकते हैं।

**ऑनलाइन कैसे अपडेट करें आधार कार्ड**

सबसे पहले आपको UIDAI के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। अब आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिये लॉग-इन करें। लॉग-इन करने के लिए आपको मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करना होगा।

इसके बाद 'आधार अपडेट' के ऑप्शन में जाकर अपना प्रोफाइल चेक करें। अब आपको जिस डिटेल्स को अपडेट करना है उसे सेलेक्ट करें।

इसके बाद ड्रॉपडाउन नेम्यू में 'I verify that the above details are



correct' के चेकबॉक्स पर टिक करना है। अब आधार अपडेट से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें और सबमिट करें।

**आधार अपडेट करने पर कितना देना होगा चार्ज**

14 दिसंबर के बाद से ऑनलाइन आधार अपडेट करने पर भी चार्ज का भुगतान करना होगा। हालांकि, अभी भी ऑफलाइन आधार कार्ड अपडेट करने के लिए अपडेशन फीस देनी होगी। UIDAI के मुताबिक आधार कार्ड में पर अपडेट के

लिए 50 रुपये का चार्ज लगता है। आधार यूजर्स ऑनलाइन एड्स प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ और नाम आदि अपडेट करवा सकते हैं। बायोमेट्रिक और फोटो अपडेट केवल ऑफलाइन ही अपडेट होगा।

## पेंशन के लिए एनपीएस है अच्छा ऑप्शन, 1.5 लाख मंथली पेंशन के लिए कितना करना होगा निवेश

रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इस स्कीम में आप जितना निवेश करते हैं उस हिसाब से आपको मैच्योरिटी के बाद पेंशन का लाभ मिलता है। हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि 1.5 लाख रुपये के मासिक पेंशन पाने के लिए आपको हर महीने कितने रुपये का निवेश करना होगा।

**नई दिल्ली** | जाँब करने के साथ ही फ्यूचर सिक्योर करने की ट्रेनिंग रहती है। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद के खर्चों को भी ट्रेनिंग बनी रहती है। ऐसे में अगर आप भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश कर सकते हैं। एनपीएस में निवेश करके आप मोटा फंड जमा कर सकते हैं। आप चाहे तो रिटायरमेंट के बाद हर महीने 1.5 लाख रुपये का पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। जी हाँ, नेशनल पेंशन सिस्टम में रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन का लाभ मिलता है। हम आपको बताएंगे कि 1.5 लाख रुपये का मासिक पेंशन पाने के लिए आपको एनपीएस में कितना निवेश करना होगा।

**हर महीने कितना करना होगा निवेश** : 1.5 लाख रुपये का मासिक पेंशन पाने के लिए आपको हर महीने 7,000 रुपये का निवेश करना होगा। एनपीएस में सालाना करीब 12 फीसदी का रिटर्न मिलता है। अगर आप 7,000 रुपये का निवेश लगातार 25 साल तक करते हैं तो 25 साल के बाद आप कुल 29,40,000 रुपये का निवेश कर चुके होंगे। इतने निवेश के साथ अगर 12 फीसदी का रिटर्न को जोड़ें तो लगभग 4.54 करोड़ रुपये का फंड जमा हो जाएगा।

इस फंड में से 40 फीसदी का इस्तेमाल एन्युटी खरीदने के लिए कर सकते हैं। बाकी 60 फीसदी बचे फंड का एकमुश्त निकाल सकते हैं। एन्युटी खरीदने के बाद आपको हर महीने करीब 1.5 लाख रुपये का पेंशन मिलेगा।

**NPS में मिलता है टैक्स बेनिफिट** : NPS का संचालन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा किया जाता है।

## 'अब हिंदी को अंतरराष्ट्रीय भाषा बनाने का गया समय' अमित शाह बोले- बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा शब्दकोष

हिंदी दिवस के अवसर गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हिंदी को एक अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि हिंदी अंतरराष्ट्रीय भाषा बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उनके अनुसार हिंदी संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनने के साथ ही 10 से अधिक देशों की द्वितीय भाषा बन चुकी है।

नई दिल्ली। हिंदी दिवस के अवसर गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हिंदी को एक अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि हिंदी अंतरराष्ट्रीय भाषा बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उनके अनुसार हिंदी संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनने के साथ ही 10 से अधिक देशों की द्वितीय भाषा बन चुकी है।

सभी भारतीय भाषाओं की सुरक्षा का केंद्र बनेगा

उन्होंने कहा कि "हिंदी शब्द सिंधु" शब्दकोष तैयार किया जा रहा है और अगले पांच साल में यह दुनिया का सबसे बड़ा शब्दकोष होगा। इस अवसर शाह ने भारतीय भाषा अनुभाग का शुभारंभ किया। शाह ने कहा कि आने वाले समय में यह सभी भारतीय भाषाओं की सुरक्षा का केंद्र बनेगा।

अमित शाह ने साफ किया कि हिंदी और स्थानीय भाषाओं के बीच कभी प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती, वे एक-दूसरे की पूरक हैं। नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में देने की मोदी सरकार की नीति का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जो देश अपनी भाषाओं की रक्षा नहीं कर पाते, वो अपने इतिहास, साहित्य व संस्कार से कट जाते हैं।

सभी भाषाओं के साहित्य, लेख और भाषणों का अनुवाद हिंदी में होगा

मातृभाषाओं को राष्ट्रीय सुरक्षा की अहम कड़ी बताते हुए शाह ने कहा कि जिन दिनों हम अपनी भाषाओं को गंवा देंगे, उस दिन देश की एकता खतरे



### हिंदी अंतरराष्ट्रीय भाषा बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है- अमित शाह

में पड़ जाएगी। भारतीय भाषा अनुभाग का शुभारंभ करते हुए अमित शाह ने कहा कि यह विभिन्न भाषाओं के बीच संवाद स्थापित करने का काम करेगा। इसके तहत हिंदी के किसी भी लेख, भाषण या पत्र में भवानुवाद देश की सभी भाषाओं में किया जाएगा और इसी प्रकार देश की सभी भाषाओं के साहित्य, लेख और भाषणों का अनुवाद हिंदी में होगा।

उन्होंने कहा कि "हिंदी शब्द सिंधु" शब्दकोष में सभी भारतीय भाषाओं के शब्दों को समाहित किया जा रहा है। मोदी सरकार के दौरान स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने की नीति का हवाला देते हुए



उन्होंने कहा कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और उत्तराखंड में मेडिकल शिक्षा का संपूर्ण

पाठ्यक्रम हिंदी में तैयार कर लिया गया है।

भारत की 13 भाषाओं में इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम तैयार करने का काम जारी

इसी तरह से भारत की 13 भाषाओं में इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम तैयार करने का काम जारी है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले दिनों में हिंदी अनुसंधान की भी भाषा होगी। राजभाषा की हीरक जयंती के अवसर पर अमित शाह ने स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्के का भी लोकार्पण किया। इस अवसर उन्होंने राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार भी प्रदान किये।

## आइपीएस अधिकारी अमृत मोहन प्रसाद बनाए गए एसएसबी प्रमुख, पहले भी निभा चुके हैं देश के लिए अहम जिम्मेदारी



वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी अमृत मोहन प्रसाद को शुक्रवार को सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का महानिदेशक नियुक्त किया गया। अमृत मोहन प्रसाद वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के विशेष महानिदेशक हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एसएसबी के महानिदेशक के पद पर प्रसाद की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2025 तक होगा जिस दिन वह सेवानिवृत्त होंगे।

नई दिल्ली। वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी अमृत मोहन प्रसाद को शुक्रवार को सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का महानिदेशक

नियुक्त किया गया। ओडिशा कैडर के 1989 बैच के आइपीएस अधिकारी अमृत मोहन प्रसाद वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के विशेष महानिदेशक हैं।

कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एसएसबी के महानिदेशक के पद पर प्रसाद की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उनका कार्यकाल 31 अगस्त, 2025 तक होगा, जिस दिन वह सेवानिवृत्त होंगे।

नेपाल और भूटान के साथ देश की सीमाओं की रक्षा करता है। एसएसबी प्रमुख दलजीत सिंह चौधरी को 28 अगस्त को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का महानिदेशक नियुक्त किए जाने के बाद यह पद खाली हुआ था।

## 'किसके आदेश पर ऐसा किया गया?' भारतीय पत्रकार के साथ कथित मारपीट को लेकर राहुल गांधी से बीजेपी के सवाल

परिवहन विशेष न्यूज

भाजपा सांसद एवं पार्टी प्रवक्ता सुधाशु त्रिवेदी ने कहा राहुल गांधी को अमेरिका यात्रा के दौरान एक पत्रकार पर हमला किया गया उसका फोन जब्त कर लिया गया। यह कांग्रेस की असली मानसिकता को बयां करता है। राहुल गांधी हर संसदीय सत्र के बाद विदेश यात्रा करते हैं और भारत विरोधी एजेंडे वाले व्यक्तियों से मिलते हैं।

नई दिल्ली। भाजपा ने अमेरिका में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एक भारतीय पत्रकार के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार की घटना को लेकर शनिवार को राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा-यह घटना कांग्रेस नेता के अमेरिका दौरे के दौरान हुई। राहुल बताए कि ऐसा किसके आदेश पर किया गया? साथ ही कहा कि पत्रकार से

दुर्व्यवहार की घटना कांग्रेस की असली मानसिकता को दर्शाती है। भाजपा सांसद एवं पार्टी प्रवक्ता सुधाशु त्रिवेदी ने कहा, राहुल गांधी को अमेरिका यात्रा के दौरान एक पत्रकार पर हमला किया गया, उसका फोन जब्त कर लिया गया और उसके द्वारा लिखा गया साक्षात्कार जबरन हटा दिया गया। यह कांग्रेस की असली मानसिकता को बयां करता है। राहुल गांधी हर संसदीय सत्र के बाद विदेश यात्रा करते हैं, भारत विरोधी बयान देते हैं और भारत विरोधी एजेंडे वाले व्यक्तियों से मिलते हैं।

एक सवाल से आप क्यों भड़क गए: राहुल गांधी भाजपा नेता ने अमेरिका में हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया में जातिवाद के बारे में गांधी की टिप्पणी की भी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा, "वह भारतीय पत्रकारों का मनोबल गिराने के लिए मीडिया में जातिवाद की बात

करते हैं और फिर उनकी टीम अमेरिका में उन पर हमला करती है। मैं राहुल से पूछना चाहता हूँ- किसके आदेश पर ऐसा किया गया? बांग्लादेशी हिंदुओं से संबंधित एक सवाल से आप क्यों भड़क गए?"

देश के खिलाफ बोलने के लिए राहुल को सबक सिखाएंगे: अठावले पीटीआई के अनुसार केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले ने शनिवार को कहा कि राहुल गांधी का आरक्षण समाप्त करने संबंधी बयान निंदनीय है और उनकी पार्टी महाराष्ट्र तथा अन्य जगहों पर कांग्रेस नेता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि दलित लोग विदेशी धरती पर देश के खिलाफ बोलने के लिए राहुल गांधी को सबक सिखाएंगे। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता से माफी मांगने की मांग भी की।

## पीएम मोदी के घर आया बेहद खास मेहमान, नाम रखा दीपज्योति

परिवहन विशेष न्यूज

पीएम मोदी के आवास में गाय के बछड़े का आगमन हुआ है। उन्होंने इस बछड़े का नाम दीपज्योति रखा है। पीएम मोदी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो बछड़े को दुलार करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर बेहद खास ब्रीड (पुंहुनर ब्रीड) की गाय है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पशु प्रेम जगजाहिर है। पीएम मोदी के आवास पर पुंहुनर ब्रीड की गाय सहित कई पालतू जानवर मौजूद हैं। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो एक गाय के बच्चे (बछड़ा) के साथ दिख रहे हैं। वीडियो में पीएम मोदी अपने घर में गाय के बछड़े को दुलार करते दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि नव वत्सा का नाम 'दीपज्योति' रखा गया है। पीएम मोदी ने नाम रखा 'दीपज्योति' प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स हैंडल पर लिखा, हमारे शास्त्रों में कहा गया है - गावः सर्वसुख प्रदाः। लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास परिवार में एक नए सदस्य का शुभ आगमन हुआ है। प्रधानमंत्री आवास में प्रिय गौ माता ने एक नव वत्सा को जन्म दिया है, जिसके मस्तक पर ज्योति का चिह्न है। इसलिए, मैंने



इसका नाम 'दीपज्योति' रखा है। पीएम आवास में मौजूद है पुंहुनर ब्रीड की गाय

इससे पहले मकर संक्रांति के मौके पर पीएम मोदी अपने आवास में गौसेवा करते नजर आए थे। प्रधानमंत्री के आवास पर बेहद खास

ब्रीड (पुंहुनर ब्रीड) की गाय है। यह दुनिया के सबसे छोटी नस्ल की गाय है। इस गाय का दूध काफी पौष्टिक माना जाता है।

## अंग्रेज अफसर के नाम पर क्यों रखा गया पोर्ट ब्लेयर का नाम? पढ़ें कौन थे आर्चीबाल्ड ब्लेयर

नई दिल्ली। पोर्ट ब्लेयर (Port Blair) का नाम बदलकर श्री विजयपुरम (Sri Vijayapuram) कर दिया गया है। औपनिवेशिक छाप से मुक्त कराने के लिए मोदी सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलने का फैसला किया है। आइए जानते हैं कि पोर्ट ब्लेयर का इतिहास क्या है और इस द्वीप का नाम पोर्ट ब्लेयर क्यों पड़ा।

दरअसल, पोर्ट ब्लेयर का नाम आर्चीबाल्ड ब्लेयर (Archibald Blair) के नाम पर रखा गया था। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नौसेना अधिकारी थे। उन्होंने 1789 में चागोस द्वीपसमूह और अंडमान द्वीपसमूह का सर्वेक्षण किया था। इसी वजह से उनके नाम पर ही पोर्ट ब्लेयर द्वीप का नाम रखा गया था।

अंग्रेजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण द्वीप था पोर्ट ब्लेयर

आर्चीबाल्ड ब्लेयर की देखरेख में पोर्ट ब्लेयर का कार्यालय किया गया। इस द्वीप को ब्रिटिश मैरिटाइम नेटवर्क का सेंटर बनाया गया। प्रशासनिक और व्यापारिक गतिविधियों पर पोर्ट ब्लेयर से ही नजर रखी जाती थी।

एक जमाने में पोर्ट ब्लेयर शहर फिशिंग का हब हुआ करता था। औपनिवेशिक शासन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीपसमूह से सुदूर इलाकों पर नजर रखा जाता था। पूर्व बंगाल की खाड़ी पर वर्चस्व बनाने के लिए पोर्ट ब्लेयर को कब्जे में लेना अंग्रेजों के लिए जरूरी था।

इस द्वीप का इतिहास

पोर्ट ब्लेयर में ही सेलुलर जेल मौजूद है, जहां ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जुल्म डार। इस जेल में काला पानी की सजा भी दी जाती थी। जेल पोर्ट ब्लेयर शहर में अटलांट प्वाइंट पर स्थित है। इस पोर्ट पर एशिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ा आरा मिल है, जिसे चायम आरा मिल कहा जाता है।

अमित शाह ने नाम बदलने के पीछे क्या है मकसद?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 'श्री विजयपुरम' नाम हमारे स्वाधीनता के संघर्ष और इसमें अंडमान और निकोबार के योगदान को दर्शाता है।

शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए पोस्ट में कहा कि देश को गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्ति दिलाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से प्रेरित होकर गृह मंत्रालय ने पोर्ट ब्लेयर का नाम 'श्री विजयपुरम' करने का फैसला लिया है। इस भारतीय द्वीप का हमारे देश की स्वाधीनता और इतिहास में अद्वितीय स्थान रहा है।

अमित शाह ने आगे कहा, "चोल साम्राज्य में नौसेना अट्टे की भूमिका अदा करने वाला यह द्वीप आज देश की सुरक्षा और विकास को गति देने के लिए तैयार है। यह द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा सबसे पहले तिरंगा फहराने से लेकर सेलुलर जेल में वीर सावरकर व अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा मां भारती की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का स्थान भी है।"

